RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 04 JANUARY TO 10 JANUARY 2023 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 08 ■ अंक 16 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

सैलरी पर खर्च हो जाता है डिफेंस बजट का 83% हिस्सा Page 2

...तो देश में थम जाएंगे विकास के पहिये Page 3

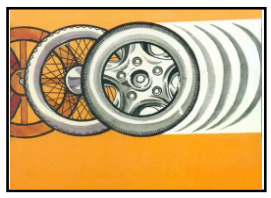

स्टार्टअप की दुनिया में रखें कदम Page 4

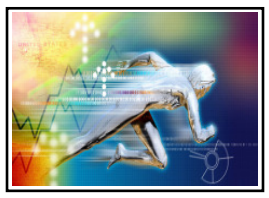

editoria!

चीन की चाल

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सीमावर्ती अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की ओर से बनाए गए एक पुल का उद्घाटन किया और 27 अन्य प्रॉजेक्ट्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास भारतीय और चीनी सैनिकों में हुई झड़प के बाद यह उनकी पहली अरुणाचल यात्रा थी। सीमा पर दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों से चल रहे टकराव के मद्देनजर भारत ने इन इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट तेज किया है। राजनाथ सिंह ने जिन प्रॉजेक्ट्स का उद्घाटन किया, ये उसी सिलसिले का हिस्सा हैं। चीन ने LAC के करीब काफी मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट किया है। इधर, कुछ वर्षों से भारत में भी इस मामले में तेजी आई है, जो चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को देखते हुए जरूरी भी है। दोनों देशों के बीच करीब 2100 मील लंबी विवादित सीमा निर्धारित नहीं हुई। 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया, उसके कुछ समय बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने भारतीय सीमाओं के आधिकारिक नक्शे के नवीनीकरण का आदेश दिया। इस नक्शे में अक्साई-चिन इलाके को भारत में पाकर चीन ने उस पर अपने कब्जे को रेखांकित करने के लिए 1957 तक उसे हाईवे से जोड़ लिया। 1962 में दोनों देशों के बीच हुआ युद्ध भी सीमा विवाद को हल नहीं कर सका। इसके बाद लंबे समय तक कोई बड़ा टकराव भले न हुआ हो, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते ठंडे ही रहे। इसमें बदलाव अस्सी के दशक में तब आना शुरू हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन यात्रा पर गए और तब के राष्ट्रपति तंग श्याओ फिंग से मिले। दोनों ने सीमा पर शांति कायम रखने के लिए बातचीत कर विश्वास बहाली वाले कदम सुझाने के लिए संयुक्त कार्य दल गठित किया। फिर 1993 में दोनों पक्षों में सीमा पर उत्पन्न होने वाले मतभेदों को सुलझाने के उद्देश्य से समझौता हुआ। इसके बाद चार और समझौते हुए। इनकी अहमियत इस बात में है कि सीमा को लेकर मतभेद रहते हुए भी बाद के करीब ढाई दशकों में कभी खून बहने की नौबत नहीं आई। माहौल बदलना शुरू हुआ 2017 में जब डोकलाम में दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने हुईं। यह गतिरोध 73 दिन चला। इसके तीन साल बाद लद्दाख स्थित गलवान घाटी में खूनी झड़प हो गई। वह मसला पूरी तरह सुलझा भी नहीं था कि तवांग सेक्टर के यांग्त्से पर कब्जा करने की चीनी कोशिश से माहौल फिर गरमा गया। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। इसमें कुछ कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी दोनों ओर से भारी संख्या में फौज वहां तैनात है। ऐसे में भारत को चौकन्ना भी रहना होगा क्योंकि चीन लगातार सीमा पर बखेड़ा खड़ा कर भारत पर दबाव बनाए रखना चाहता है।

चीनी मिलों के भीतर भी पेट्रोल बेचने की ख्वाहिश

नई दिल्ली । एजेंसी

चीनी कारखाने एथनॉल की खपत को बढ़ावा देने और कमाई का नया जरिया तैयार करने के लिए चीनी कारखाने अपनी उत्पादन इकाइयों को ऊर्जा केंद्र (एनर्जी हब) में बदलने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसके तहत वे एथनॉल मिला पेट्रोल बेचेंगे, आसपास के इलाकों की रसोई गैस की मांग पूरी करने के लिए बायो-सीएनजी बनाएंगे और बेचेंगे तथा स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए बायो-सीएनजी और स्थानीय उपभोक्ताओं के लिए कई तरह की ऊर्जा के केंद्र बनेंगे। इनके ज्यादातर ग्राहक किसान हो सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इस प्रस्ताव के खाके पर उद्योग के शीर्ष अधिकारियों और इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) तथा नैशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (एनएफसीएसएफ) जैसे संगठनों के बीच चर्चा हो चुकी है। इस्मा तो चाहता है कि पहले इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता और लागत के मुकाबले होने वाला लाभ जांचने का काम किसी पेशेवर एजेंसी को दिया जाए। उसके बाद ही वित्तीय सहायता और जरूरी मंजूरी हासिल करने के लिए केंद्र सरकार से बात की जाए।

इस्मा के प्रेसिडेंट आदित्य झुनझुनवाला के अनुसार इस योजना का मकसद देश भर में गांवों के बीच में बनी 500 के करीब चीनी मिलों को पेट्रोल पंप खोलने लायक बनाना है। इन पंपों से एथनॉल मिला पेट्रोल बेचा जाएगा, घरेलू ग्राहकों के लिए बायो-सीएनजी बनाई तथा बेची जाएगी और मिल परिसर में ही ई-वाहनों की चार्जिंग के केंद्र भी बनाए जाएंगे।

अगर ग्रामीण इलाकों में ऐसे फ्लेक्स-फ्यूल पर चलने वाले वाहन मौजूद हों तो 20 फीसदी से भी अधिक एथनॉल वाला पेट्रोल इन पंपों से बेचा जा सकता है। सिंचाई पंप बनाने वाली अग्रणी कंपनियों से तो एथनॉल से चलने वाले पंप बनाने के लिए बात भी शुरू हो गई है। इन पंपों को ऐसे कारखानों से रीफिल कराया जा सकता है।

झुनझुनवाला ने न्यूज एजेंसी से कहा, 'हमारी मिलों में गन्ना पहुंचाने के लिए हर साल हजारों ट्रैक्टर आते हैं। यदि उन्हें कारखाने के भीतर ही एथनॉल मिला पेट्रोल मिल जाए तो कंपनियों के लिए कमाई का अच्छा स्रोत हो सकता है। इससे एथनॉल को तेल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के डिपो तक पहुंचाने में होने वाला खर्च भी बच सकता है।' उन्होंने कहा कि चीनी कारखानों से 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले किसानों को ऐसे ईंधन की खुदरा बिक्री और दूसरी सेवाओं से बहुत राहत मिल सकती है।

एनएफसीएसएफ के महानिदेशक प्रकाश नाइकनवरे ने कहा कि अभी पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का काम ओएमसी के डिपो में किया जाता है, जो काम चीनी मिलों में भी हो सकता है। इससे चीनी कंपनियों को कमाई का एक और जरिया मिल जाएगा। उन्होंने कहा, 'एनएफसीएसएफ पूरी तरह इस विचार का समर्थन करता है। उद्योग के साथ बातचीत में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कई बार इसका समर्थन किया है।'

झुनझुनवाला ने कहा कि देश भर में लगी 500 के करीब चीनी मिलों में से हरेक मिल अगर अपने परिसरों में कम से कम पांच पेट्रोल पंप लगाती है तो देश में 2,500 ऐसे पंप लग जाएंगे, जो 20 फीसदी से अधिक एथनॉल वाला पेट्रोल बेचेंगे। उन्होंने कहा, 'ब्राजील में ऐसे वाहन हैं जो 100 फीसदी एथनॉल पर चल सकते हैं। हमने भी पूरी तरह एथनॉल पर चलने वाले ट्रैक्टर और अन्य मशीनें तैयार करने के लिए वाहन उद्योग से बात शुरू कर दी है।' झुनझुनवाला ने कहा कि मांग बढ़ी तो चीनी उद्योग अपने अतिरिक्त उत्पादन में से 1 करोड़ चीनी रोककर 10 अरब लीटर एथनॉल भी बना सकता है।

फिलहाल सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20 फीसदी एथनॉल मिलाने का महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसके लिए देश में लगभग 14.5 अरब लीटर (10.5 अरब लीटर केवल पेट्रोल में मिलाने के ही लिए) एथनॉल की उत्पादन क्षमता हासिल करनी होगी। बाकी उत्पादन स्टार्च और रसायन उद्योग के लिए अलग रखना होगा। मोटा अनुमान यह है कि 7.6 अरब लीटर एथनॉल गन्ने से बनाना होगा और 7.2 अरब लीटर एथनॉल अनाज तथा उससे इतर स्रोतों जैसे धान की ठूंठ आदि से आएगा।

कच्चा तेल 3 डॉलर सस्ता

कई शहरों में घट गए पेट्रोल-डीजल के दाम

नई दिल्ली । एजेंसी

ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है और पिछले 24 घंटे के दौरान ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 3 डॉलर गिर गया है। इसका असर बुधवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों की ओर से जारी पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों पर दिखा और आज कई शहरों में तेल सस्ता हो गया है। हालांकि, दिल्ली-मुंबई जैसे देश के चारों महानगरों में आज भी पेट्रोल-डीजल के रेट नहीं बदले हैं। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज पेट्रोल के भाव में 83 पैसे सस्ता हुआ और 108.481 रुपये लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल 75 पैसे सस्ता होकर 93.72 रुपये लीटर बिक रहा है। हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में भी आज पेट्रोल 5 पैसे गिरकर 96.89 रुपये लीटर और डीजल 6 पैसे गिरकर 89.76 रुपये लीटर बिक रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान इसकी कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 3 डॉलर गिरकर 82.43 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया है। वहीं, डब्ल्यूटीआई का भाव ढाई डॉलर टूटकर 77.22 डॉलर प्रति बैरल हो गया है।

चारों महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम

- दिल्ली में पेट्रोल 96.65 रुपये और डीजल 89.82 रुपये प्रति लीटर
- मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर
- चेन्नई में पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर
- कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर

चीन और पाकिस्तान से कैसे होगा मुकाबला

सैलरी पर खर्च हो जाता है डिफेंस बजट का 83% हिस्सा

नई दिल्ली । एजेंसी

सेना लंबे समय से डिफेंस बजट में बढ़ोतरी की मांग कर रही है। इसकी वजह यह है कि भारत को पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन के साथ लंबे समय से सीमा पर तनातनी चल रही है। सेना को दो मोर्चों पर एक साल निपटने के लिए अपनी तैयारी करनी पड़ रही है। लेकिन उसमें बजट की कमी लगातार आड़े आ रही है।

दूसरी ओर पाकिस्तान और चीन लगातार अपने डिफेंस बजट में इजाफा कर रहे हैं। पिछले साल के आम बजट में डिफेंस के लिए 5.2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इसमें से सबसे ज्यादा 1.9 लाख करोड़ रुपये आर्मी के लिए आवंटित किए गए थे। लेकिन इसका 83 फीसदी हिस्सा सैलरी और रोजाना के खर्चों में चला जाता है। केवल 17 फीसदी हिस्सा ही सेना के आधुनिकीकरण के लिए बच जाता है। इतना ही नहीं कुल डिफेंस बजट में से 1.2 लाख करोड़ रुपये 33 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और डिफेंस सिविलियन के पेंशन में चला गया। इससे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त रकम नहीं बचती है। सेना के पास मॉडर्न इंफेंट्री वेपन्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, हॉवित्जर्स, रात में लड़ने में सक्षम क्षमताओं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों और साजो-सामान की भारी कमी है। साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे नीचे के फाइटिंग रैंक के अधिकारियों की भी कमी है। दरअसल, सैलरी और पेंशन पर खर्च बढ़ने के कारण सेना को अपने आधुनिकीकरण के लिए बहुत कम बच पाता है जिससे अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया जा सके।

सैलरी और पेंशन पर भारी-भरकम खर्च

आर्मी में इस समय करीब 12 लाख अधिकारी और जवान हैं। इनमें अधिकारियों की संख्या करीब 43,000 है। सेना को छह ऑपरेशनल और एक ट्रेनिंग कमान में बांटा गया है। छह कमान में 14 कोर, 50 डिवीजन और 240 से अधिक ब्रिगेड हैं। संख्या बल के आधार पर तीनों सेनाओं में थल सेना सबसे बड़ी है लिहाजा पेंशन और वेतन के मद में इसका खर्च भी सबसे अधिक है। भारत अपने डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा सैनिकों के वेतन और पेंशन पर खर्च करता है। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों में सेना का पेंशन पर खर्च इससे कहीं कम है। सरकार का लक्ष्य है कि इस मद में खर्च को कम करने सेना के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जाए।

अग्निपथ योजना का मकसद वेतन और पेंशन के मद में खर्च की जा रही भारी-भरकम राशि को भी कम करना है। वित्त वर्ष 2013-14 में देश की जीडीपी का आकार 112 लाख करोड़ रुपये था जो 2022-23 में 237 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया।

इस दौरान सैनिकों के वेतन पर किया जाने वाला खर्च स्थिर रहा लेकिन एक जुलाई, 2014 को वन रैंक वन पेंशन लागू करने के बाद भी पेंशन खर्च बढ़ता रहा। साल 2013-14 में सैनिकों के वेतन और पेंशन पर खर्च की डिफेंस बजट में हिस्सेदारी 42.2 फीसदी थी जो 2021-22 में 48.4 फीसदी पहुंच गई।

चीन और पाकिस्तान का डिफेंस बजट

चीन अपने रक्षा बजट का केवल 30.8 फीसदी ही वेतन और पेंशन पर खर्च करता है। इस मामले में इटली 65.7 प्रतिशत के साथ पहले नंबर पर है। पाकिस्तान के मामले में 37 फीसदी है जबकि अमेरिका अपने डिफेंस बजट का 38.6 फीसदी हिस्सा सैनिकों की सैलरी और पूर्व सैनिकों की पेंशन पर खर्च करता है। जीडीपी के अनुपात में सैन्य खर्च की बात करें तो अमेरिका इस मामले में पहले नंबर पर है। साल 2021 में उसने अपनी जीडीपी का 3.5 फीसदी हिस्सा डिफेंस पर खर्च किया। चीन में मामले में यह 1.7 फीसदी और पाकिस्तान के मामले में 3.8 फीसदी है। भारत ने 2021 में अपनी जीडीपी का 2.7 फीसदी हिस्सा डिफेंस पर खर्च किया। इस मामले में रूस पहले नंबर पर रहा। उसने अपनी जीडीपी का 4.1 फीसदी हिस्सा डिफेंस पर खर्च किया। चीन का रक्षा बजट 2022 में 261 अरब डॉलर का था।

आईसीआईसीआई बैंक ने बढ़ाया एफडी पर ब्याज, ग्राहक होंगे मालामाल

इंदौर । एजेंसी

निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई ने नए साल में अपने ग्राहकों को तोहफा देते हुए फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान किया है। अब ग्राहकों को फिक्स डिपाजिट कराने पर पहले से अधिक मुनाफा होगा। बैंक ने बल्क एफडी का इंटरस्ट रेट बढ़ा दिया है। अब 2 करोड़ रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक के फिक्स डिपॉजिट पर पहले से अधिक ब्याज मिलेगा।

आईसीआईसीआई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर नई दरें अपलोड कर दी गई हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि यह 2 जनवरी 2023 से प्रभावी है। ब्याज दरों में होने वाले बदलाव के बाद 7 दिन से 10 वर्ष तक में परिपक्व होने वाले फिक्स डिपॉजिट पर 4.5 फीसद से लेकर 6.75 फीसद तक का ब्याज मिल पाएगा।

क्या हैं नई दरें

15 महीने से लेकर 2 साल के बीच की अवधि के फिक्स डिपॉजिट पर आईसीआईसीआई बैंक 7.5 फीसद का ब्याज देगा। इसके अलावा 7 दिन से लेकर 29 दिन में मच्योर होने वाली थोक एफडी पर 4.5 फीसद और 30 दिन से 45 दिन में परिपक्व होने वाली एफडी पर 5.25 फीसद की दर से ब्याज मिलेगा। 46 से 60 दिन की एफडी के लिए बैंक 5.5 फीसद की ब्याज ऑफर कर रहा है, जबकि 61 दिन से लेकर 90 दिन की अवधि वाली एफडी के लिए 5.75% की दर से ब्याज दिया जाएगा। 91 से 184 दिन में मैच और होने वाली एफडी पर 6.25 परसेंट का ब्याज मिलेगा, जबकि 185 से 270 दिन वाली एफडी पर 6:30 फीसद ब्याज मिलेगा।

इन योजनाओं पर मिलेगा सबसे अधिक ब्याज

आईसीआईसीआई बैंक की ओर से कहा गया है कि 271 दिन से लेकर 1 साल से कम अवधि की फिक्स डिपॉजिट पर 6.65 फीसद की दर से ब्याज दिया जाएगा, जबकि 1 साल से 1 साल 3 महीने की अवधि वाले डिपॉजिट पर 7.10 प्रतिशत के हिसाब से ग्राहक ब्याज का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक 15 महीने से लेकर 24 महीने तक की एफडी पर 7.15 फीसद की दर से ब्याज देगा। 2 साल 1 दिन से लेकर 3 साल तक की डिपॉजिट पर 7 फीसद और 3 साल से 10 साल के बीच में परिपक्व होने वाली एफडी पर 6.5 फीसद की दर से ब्याज दिया जाएगा।

ये दरें भी बदलीं

आईसीआईसीआई बैंक से अधिक की उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को एफबी पर 7:30 फीसद की ब्याज ऑफर रहा है। आपको बता दें कि सीनियर सिटीजन को मिलने वाला ब्याज सामान्य लोगों को दिए जाने वाले ब्याज से अधिक होता है। इसकी वजह यह है कि बैंक और सरकार सीनियर सिटीजन के योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरें ऊंची रखते हैं।

खाद्य सब्सिडी में 17 अरब डॉलर की कटौती का लक्ष्य

नई दिल्ली । एजेंसी

अप्रैल से वित्त वर्ष में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर खर्च को घटाकर 3.7 लाख करोड़ रुपये (44.6 अरब डॉलर) करना भारत का लक्ष्य है। यह इस वर्ष से 26इ कम है। दो सरकारी अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाने के लिए ऐसा किया जाएगा। खाद्य और उर्वरक सब्सिडी इस वित्तीय वर्ष में भारत के 39.45 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट खर्च का लगभग आठवां हिस्सा है, लेकिन विशेष रूप से खाद्य सब्सिडी में कटौती चुनावों के साथ राजनीतिक रूप से संवेदनशील साबित हो सकती है। दोनों अधिकारियों ने कहा कि सरकार को खाद्य सब्सिडी के लिए इस वर्ष के 31 मार्च तक 2.7 लाख करोड़ रुपये की तुलना में आगामी वित्त वर्ष में करीब 2.3 लाख करोड़ रुपये के बजट की उम्मीद है। एक अधिकारी और एक तीसरे सरकारी अधिकारी के अनुसार, उर्वरक सब्सिडी पर खर्च लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये तक कम होने की संभावना है। तीसरे अधिकारी ने कहा कि इस साल इसकी तुलना करीब 2.3 लाख करोड़ रुपये से की जा सकती है। जानकारी सार्वजनिक नहीं होने के कारण अधिकारियों ने नाम बताने से इनकार किया है। वित्त मंत्रालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि खाद्य और उर्वरक मंत्रालयों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया। पहले दो अधिकारियों ने कहा कि बचत का एक बड़ा हिस्सा एक कोविड-19 युग की मुफ्त भोजन योजना के अंत से आएगा, जिसे कम खर्च वाले कार्यक्रम से बदल दिया जाएगा। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए उत्सुक है, जो चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 फीसदी पर लक्षित है।

1000 रु. को बनाया 76.4 करोड़ 14 साल की हुई बिटकॉइन

नई दिल्ली । एजेंसी

क्रिप्टोकरेंसी का नाम आते ही दिमाग में सबसे पहले बिटकॉइन (Bitcoin) का नाम आता है। बिटकॉइन दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है। क्रिप्टोकरेंसी का पर्याय बन बिटकॉइन आज 14 साल पूरे कर लिए हैं। यूं तो बिटकॉइन के वर्चुअल क्रिएटर सतोशी नाकामोतो (Satoshi Nakamoto) ने 28 अक्टूबर, 2008 को इसका व्हाइटपेपर जारी किया था लेकिन उसकी मिंट डेट तीन जनवरी, 2009 थी। यही वजह है कि कई लोग तीन जनवरी को ही बिटकॉइन का बर्थडे मानते हैं। अपने 14 साल के सफर में बिटकॉइन ने कई उतारचढ़ाव देखे हैं। दुनिया के कई देशों ने अब भी इसे औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है लेकिन इससे इसका क्रेज कम नहीं हुआ है।

दुनियाभर में क्रिप्टोकरेंसीज और ब्लॉकचेन के उभार में बिटकॉइन की सबसे अहम भूमिका है। नाकामोतो ने 3 जनवरी को बिटकॉइन का ऑरिजिनल ब्लॉक रिलीज किया था जिसे अब जेनेसिस ब्लॉक (Genesis Block) के नाम से जाना जाता है। इसमें पहली 50 बिटकॉइन थीं। इसका पहला ट्रांजैक्शन मई 2009 में हुआ था। इसका मकसद दुनिया में एक ऐसी करेंसी लाना था जिसमें बैंकों और दलालों की कोई भूमिका नहीं होगी। coinmarketcap.com के मुताबिक बिटकॉइन की कीमत अभी 16,748 डॉलर यानी करीब 13,88,266 रुपये है।

एक हजार को बनाया 76.43 करोड़

बिटकॉइन के लिए पिछले 14 साल काफी उतार-चढ़ाव वाले रहे। इस दौरान इसने कई दोस्त और दुश्मन बनाए। बिटकॉइन के अब तक के रिटर्न को कैलकुलेट करना असंभव है क्योंकि इसकी शुरुआत जीरो के साथ हुई थी। जुलाई 2010 में इसकी कीमत 0.09 डॉलर थी और नवंबर 2021 में यह 68,790 डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंची थी। पिछले 14 साल में भारी भरकम रिटर्न दिया है। यानी शुरुआत में इसमें 1,000 रुपये का निवेश नवंबर 2021 में 76.43 करोड़ रुपये बन गया होता। हाल के वर्षों में बिटकॉइन के निवेशकों में काफी बदलाव आया है। अब रिटेल के बजाय इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स इसमें दांव लगा रहे हैं।

साल 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुई थी तब इसकी कीमत मात्र 0.060 रुपये थी। इसकी कीमत में पहली बार तेजी साल 2010 में आई थी जब इसकी कीमत 0.0008 डॉलर से बढ़कर 0.08 डॉलर पहुंची थी। इसके बाद अप्रैल 2011 में इसकी कीमत एक कडॉलर थी जो जून में बढ़कर 32 डॉलर हो गई।

बिटकॉइन के लिए साल 2013 बेहद निर्णायक रहा। तब दो बार इसकी कीमत में भारी उछाल आई। अप्रैल 2013 में इसका भाव 220 डॉलर पर पहुंच गया। बिटकॉइन की कीमतों में बड़ा उछाल 2017 में आया। जून 2019 में इसका भाव 10 हजार डॉलर के पास था। वहीं, जनवरी 2021 में इसने 40 हजार डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया और फिर उसी साल नवंबर में यह रेकॉर्ड हाई पर पहुंच गई थी।

निवेशकों ने दिखाई दिलचस्पी

इंस्टीट्यूशनल और रिटेल निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी का ही नतीजा है कि बिटकॉइन का मार्केट कैप एक लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच चुका था। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी टेस्ला (Tesla) के साथ-साथ Square और MicroStrategy जैसी कंपनियों ने भी बिटकॉइन को सपोर्ट किया है। Morgan Stanley अपने कुछ अमीर ग्राहकों को बिटकॉइन फंड्स का एक्सेस देने वाला पहला बैंक बना था।

साल 2021 में लैटिन अमेरिकी देश अल साल्वाडोर (El Salvador) बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश बना था। वहां गुड्स और टैक्स के पेमेंट में बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में पहले बिटकॉइन ईटीएफ ने 'BITO' के नाम से शुरुआत की गई थी। हालांकि हाल के दिनों में इसमें भारी गिरावट आई है। इसकी वजह यह है कि दुनियाभर की सरकारों खासकर अमेरिका ने इसे हतोत्साहित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब इसका मार्केट कैप 318.80 अरब डॉलर रह गया है जो एक साल पहले 874.90 अरब डॉलर था। यानी पिछले एक साल में इसमें 63.5 फीसदी गिरावट आई है।

यमन में तेल सुविधाएं 21.6 मिलियन डॉलर के सौदे में हाथ बदले

यमन । एजेंसी

एक वैश्विक ऊर्जा कंपनी ने मंगलवार को एक अन्य अंतरराष्ट्रीय फर्म से युद्धग्रस्त यमन में तेल उत्पादन सुविधाओं का अधिग्रहण किया। यह कदम ऐसे समय आया है जब देश के हौथी विद्रोहियों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को तेल निर्यात करने से रोकने के प्रयासों में बार-बार टर्मिनलों और टैंकरों को निशाना बनाया है। जेनिथ एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी जेनिथ नीदरलैंड ने घोषणा की कि वह 21.6 मिलियन डॉलर से अधिक के सौदे में यमन में वियना स्थित ओएमवी की ऊर्जा संपत्ति हासिल करने पर सहमत हो गई है।

सौदा अभी भी यमन और ऑस्ट्रिया में अधिकारियों के अनुमोदन के लिए लंबित है। यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई। जेनिथ के सीईओ एंड्रिया कट्टानेओ ने कहा, 'ओएमवी यमन का अधिग्रहण जेनिथ एनर्जी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है।' 'संपत्ति से मौजूदा उत्पादन और, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, निकट भविष्य में तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन ... जेनिथ को एक अत्यंत रोमांचक जैविक विकास पथ पर स्थित करता है।

जेनिथ नीदरलैंड द्वारा घोषित सौदे के अनुसार, मध्य यमन में अल-उकलाह तेल क्षेत्र में ओएमवी की सबसे बड़ी संपत्ति इसके शेयर थे, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा नियंत्रित है। घोषणा में कहा गया है कि ड्रिलिंग गतिविधियों की कमी के कारण इस क्षेत्र ने जनवरी 2022 तक औसतन 6,000 बैरल प्रति दिन का उत्पादन किया। यमन के गृह युद्ध से पहले यह राशि लगभग 15,000 बैरल प्रति दिन से कम थी। घोषणा में कहा गया है कि ओएमवी ने केंद्रीय यमन में दो छोटे क्षेत्रों में अपने शेयरों को 571 बिलियन क्यूबिक फीट वसूली योग्य गैस के साथ बेचा। यमन का युद्ध 2014 में शुरू हुआ जब ईरान समर्थित हौथी विद्रोही उत्तर में अपने गढ़ से उतरे, राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को निर्वासन में सऊदी अरब भागने के लिए मजबूर कर दिया। अगले वर्ष, सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने युद्ध में प्रवेश किया, जिसका उद्देश्य हौथियों को हटाना था। ध्श्न सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा फर्मों में से एक थी जो अभी भी यमन में काम कर रही है। इसने जून में घोषणा की कि वह अपनी तेल गतिविधियों को कम करने की योजना के तहत देश में अपनी संपत्ति बेचेगा।

फर्म ने बताया कि यमन में इसका तेल और गैस उत्पादन 2021 में 15% घटकर 1.1 मिलियन बैरल रह गया, जो मारिब के ऊर्जा-समृद्ध केंद्रीय प्रांत पर हौथी आक्रमण की ऊंचाई पर था। चूंकि युद्धरत पक्ष अक्टूबर में यूएन-ब्रोकेड ट्रूस को नवीनीकृत करने में विफल रहे, विद्रोहियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा तेल निर्यात को रोकने के प्रयास में देश में काम कर रहे तेल टर्मिनलों और ऊर्जा फर्मों पर बार-बार हमला किया।

...तो देश में थम जाएंगे विकास के पहिये

नई दिल्ली । एजेंसी

आरबीआई ने राज्यों के बढ़ते सब्सिडी बिल पर चिंता जताई है। उसका कहना है कि अगर सब्सिडी पर लगाम नहीं लगाई तो देश में विकास के पहिए थम जाएंगे। केंद्रीय बैंक ने अपनी Financial Stability Report, दिसंबर 2022 में यह बात कही है। इसमें कहा गया है कि अगर राज्यों का सब्सिडी बिल इसी तरह बढ़ता रहा तो उनके पास डेवलपमेंट और कैपिटल स्पेंडिंग के लिए पैसा नहीं बचेगा। फाइनेंशियल ईयर 2021 में सब्सिडी पर राज्यों के खर्च में 12.9 फीसदी और 2022 में 11.2 फीसदी बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2020 में इसमें गिरावट आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में राज्यों के कुल रेवेन्यू खर्च में सब्सिडी का हिस्सा 7.8 फीसदी था जो 2021-22 में बढ़कर 8.2 फीसदी पहुंच गया।

केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्यों में सब्सिडी में भारी बढ़ोतरी हुई है। यह चिंता की बात है। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में भी कुछ राज्यों के रेवेन्यू खर्च में सब्सिडी का हिस्सा बढ़ने पर चिंता जताई गई है। कई राज्यों में लोगों को मुफ्त बिजली और पानी दिया जा रहा है। इसी तरह कुछ राज्यों में मामूली कीमत पर राशन बांटा जा रहा है। इस साल आई इंडिया रेटिंग्स (India Ratings) की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सहित पांच राज्य गंभीर आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। इसकी वजह यह है कि इन राज्यों के सब्सिडी का हिस्सा काफी बढ़ चुका है। इनमें पंजाब के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार शामिल हैं।

महंगाई काबू में आने की उम्मीद

एजेंसी के चीफ इकनॉमिस्ट देवेंद्र पंत ने कहा कि कंप्टीटिव पॉलिटिक्स के कारण राज्य खासकर नॉन-मेरिट सब्सिडी पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। शिक्षा के अलावा अधिकांश सब्सिडी को नॉन-मेरिट माना जाता है। देश में राजनीतिक दल चुनावों में रेवड़ियां बांटने का वादा करते हैं और सत्ता में आने पर इस वादे को पूरा करते हैं। इसका बोझ सरकारी खजाने पर पड़ता है। इससे सरकार के पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं रह जाता है। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह सार्वजनिक तौर पर इसका विरोध कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी देश में बढ़ते रेवड़ी कल्चर पर चिंता जताई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की खुदरा महंगाई जनवरी से लगातार संतोषजनक सीमा से ऊपर रहने के बाद अब नरम हुई है और इसे काबू में लाने के लिए जिस तत्परता से कदम उठाए गए हैं, उससे इसके और नीचे आने की उम्मीद है। हालांकि इसमें कहा गया है कि मुख्य (कोर) महंगाई के बने रहने और इसके बढ़ने से दबाव बना रह सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'आरबीआई ने मंहगाई को काबू में लाने के लिये तत्परता से कदम उठाए हैं। इससे मुद्रास्फीति के संतोषजनक दायरे और लक्ष्य के करीब आने की उम्मीद है। साथ ही इससे महंगाई को लेकर जो आशंकाएं हैं, उस पर भी लगाम लगेगी।'

क्यों बढ़ती है महंगाई

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिकूल वैश्विक हालात का सामना कर रही है। लेकिन मजबूत वृहत आर्थिक बुनियाद और वित्तीय एवं गैर-वित्तीय क्षेत्र के मजबूत बही-खाते के चलते वित्तीय प्रणाली बेहतर स्थिति में है। हालांकि, महंगाई ऊंची बनी हुई है, लेकिन तेजी से उठाए गए मौद्रिक नीति कदम और आपूर्ति के स्तर पर हस्तक्षेप से अब इसमें नरमी आ रही है। आरबीआई ने कहा कि अमेरिकी डॉलर में मजबूती से आयात महंगा होने के कारण भी महंगाई बढ़ती है। इससे खासकर उन जिंसों के दाम बढ़ते हैं, जिन वस्तुओं का आयात डॉलर में किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक रुपये की विनिमय दर में गिरावट से स्थानीय मुद्रा में जिंसों के दाम में तेजी अभी भी बनी हुई है और कई अर्थव्यवस्थाओं में यह औसतन पिछले पांच साल के मुकाबले ऊंची बनी हुई है। गरीब अर्थव्यवस्थाओं के लिये यह दोहरा झटका है। इससे एक तरफ जहां जिंसों के दाम बढ़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ इससे मानवीय संकट भी पैदा होता है। घरेलू वित्तीय स्थिति के बारे में आरबीआई ने कहा कि महंगाई को लक्ष्य के अनुसार संतोषजनक दायरे में लाने के लिए मौद्रिक नीति को सख्त किया है।

एनपीए पर अच्छी खबर

आरबीआई को महंगाई दो से छह प्रतिशत के बीच रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। केंद्रीय बैंक द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के समय मुख्य रूप से खुदरा महंगाई पर गौर करता है। यह इस साल जनवरी से संतोषजनक स्तर की उच्च सीमा यानी छह प्रतिशत से ऊपर बने रहने के बाद नवंबर में नरम होकर 5.88 प्रतिशत पर आई है। इस बीच बैंकों का सकल एनपीए यानी फंसा कर्ज सात वर्षों के निचले स्तर पांच प्रतिशत पर आ गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक व्यवस्था मजबूत बनी हुई है और उनके पास पर्याप्त पूंजी है।

भारत-आस्ट्रेलिया ईसीटीए होने के बाद पहला कंसाइनमेंट रवाना

मुंबई । एजेंसी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता 29 दिसंबर 2022 से लागू हो गया है। दोनों देशों के बीच हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत रत्न एवं आभूषण की पहली खेप को हरी झंडी भी दिखा दी गई। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। उन्होंने इसके तहत मुंबई, सूरत और चेन्नई से एक साथ कंसाइनमेंट को रवाना किया।

आस्ट्रेलिया में निर्यात की बड़ी संभावना

इस अवसर पर गोयल ने कहा कि इस समझौते के लागू होने के साथ ही आस्ट्रेलिया के साथ भारत ने दो समझौते किए, वह भी एक कैलेंडर वर्ष के भीतर। यह हम सबके लिए बड़े हर्ष और उत्सव की बात है। देखा जाए तो आस्ट्रेलिया को फिनिश्ड गुड्स के निर्यात की काफी संभावनाएं हैं। वहां बड़े पैमाने पर रॉ मैटेरियल और इंटरमीडियरी गुड्स का प्रोडक्शन होता है। भारत में फिनिश्ड गुड्स के निर्माण में काफी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी राजेश कुमार ने कहा कि इस ईसीटीए से दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी एक साथ आ गए हैं। देखा जाए तो इन दोनों देशों की प्रकृति एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के पास रॉ मैटेरियल का भंडार है तो एक के पास मैन्यूफैक्चरिंग गुड्स बनाने में प्रवीणता। इस समझौते के जरिए आस्ट्रेलिया से जीरो ड्यूटी पर रॉ मैटेरियल का आयात होगा। इससे हमारे मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को भारी बढ़ावा मिलेगा।

जेम एंड ज्वैलरी सेक्टर में आएगी तेजी

इस अवसर पर जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल के अध्यक्ष विपुल शाह ने कहा कि यह भारत सरकार की एक और सराहनीय उपलब्धि है। यह समझौता रत्न और आभूषण क्षेत्र के विकास में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने अनुमान जताया कि भारत-आस्ट्रेलिया ईसीटीए अगले तीन वर्षों में द्विपक्षीय रत्न और आभूषण व्यापार को 1.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वर्तमान मूल्य से दोगुना करके 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर ला देगा। आस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाने वाले सोने और चांदी के ज्वैलरी के साथ साथ इमिटेशन ज्वैलरी पर 0% ड्यूटी लगने से इन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। इससे एक बिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त व्यापार की संभावना बनेगी।

स्टार्टअप की दुनिया में रखें कदम

जानिए इसकी पूरी ABCD

नई दिल्ली । एजेंसी

अगर कोई शख्स जॉब नहीं करना चाहता या उसे सही जॉब नहीं मिल पा रही है लेकिन वह अपने काम को 100 नहीं, 200 फीसदी मेहनत और बढ़िया प्लानिंग के साथ पूरा कर सकता है तो स्टार्टअप की दुनिया में स्वागत है। हम इस लेख में जानेंगे कि स्टार्टअप कैसे शुरू करें। कैसे पता चले कि हम भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं या नहीं? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी बारे में देश के जाने-माने एक्सपर्ट्स से बातचीत करके पूरी जानकारी दे रही हैं रजनी शर्मा। भारत में अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो गया है। फिन टेक, हेल्थ, स्पेस, एग्रो, इंडस्ट्री, सिक्युरिटी, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, एडटेक और फूड आदि क्षेत्रों में काफी स्टार्टअप काम कर रहे हैं। हाल का एक सर्वे बताता है कि भारत में 61,400 स्टार्टअप हैं जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) द्वारा मान्यता मिली हुई है। इसमें से करीब 14,000 स्टार्टअप ऐसे हैं जिन्हें 2021-22 में ही मान्यता मिली है। 44 भारतीय स्टार्टअप ऐसे हैं जिन्हें साल 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल हुआ और चालू वित्त वर्ष 2022-23 में ऐसे 100 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। कोई स्टार्टअप यूनिकॉर्न तब कहलाता है जब उसकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर के पार हो जाए।

स्टार्टअप का सही वक्त

हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं। अब इंटरनेट की वजह से कम पैसे में चीजों को बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। भारत में पिछले 20 साल में स्टार्टअप की लागत भी कम हुई है। टेक्नॉलजी की वजह से काम करना आसान हो गया है। लेकिन हम अपना स्टार्टअप या बिजनेस कैसे शुरू करें और सारी मुश्किलों को पार करते हुए उसे कामयाब कैसे बनाएं?

हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। स्टार्टअप शुरू करने के कई अहम कदम होते हैं। जब हम इनके बारे में जान लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले तो हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि हम स्टार्टअप के लिए तैयार भी हैं या नहीं?

पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं

• **आंत्रप्रेन्योर** - ऐसा शख्स जो मार्केट में आए नए मौके के मुताबिक ऐक्शन ले। बाजार की अलग-अलग प्रॉडक्ट कैटिगरी में वह फटाफट कदम रखता है। वह स्टार्टअप शुरू करता है।

• **आंत्रप्रेन्योरशिप** - यह प्रक्रिया एक बिजनेस की प्लानिंग करने, टीम बनाने और फिर कस्टमर की जरूरतों को पूरा करने व शेयरहोल्डर्स के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए नए-नए तरीकों से बिजनेस चलाने से शुरू होती है।

स्टार्टअप और बिजनेस में फर्क

कभी-कभी स्टार्टअप और बिजनेस जैसे शब्दों को एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लिया जाता है लेकिन ये दोनों अलग हैं। स्टार्टअप और छोटा बिजनेस करना दोनों अलग बातें हैं। स्टार्टअप वह बिजनेस मॉडल है जो कोई बिजनेसमैन नए आइडिया और किसी परेशानी को हल करने के मकसद से शुरू करता है, जैसे ऑनलाइन पैसों का ट्रांसफर करना। इसमें आइडिया और इनोवेशन दोनों चीजें अहम होती हैं, जबकि छोटा बिजनेस वह मॉडल है जिसके जरिए कोई पारंपरिक व्यवसाय में ही अपनी बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करता है। वह लोकल लेवल पर होता है जैसे किराने की दुकान। इसका मतलब है कि कोई बिजनेस वह जो पहले से चल रहा है और स्टार्टअप नए विचार या नई तकनीक से पैदा होता है। वह स्टार्टअप तभी है जब वह कोई नया बिजनेस होगा।

ऐसे गुण होते हैं आंत्रप्रेन्योर में

आप बिजनेस चलाना चाहते हैं या स्टार्टअप? अगर आंत्रप्रेन्योर बनना है तो क्या आपके अंदर सही काबिलियत है? इसलिए कामयाब आंत्रप्रेन्योर के गुण जान लेते हैं। एक कामयाब आंत्रप्रेन्योर में ऐसे गुण होते हैं जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा होते हैं और कामयाबी दिलाते हैं। ये उन्हें जीवन में कामयाब होने में मदद तो करते ही हैं, साथ ही आंत्रप्रेन्योरशिप के दौरान आनेवाली मुश्किलों को दूर करने में भी मदद करते हैं:

क्या आप में है कॉन्फिडेंस?

आत्मविश्वास किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे जरूरी क्षमता है। इसका यह भी मतलब है कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना। आत्मविश्वास एक आंत्रप्रेन्योर को कस्टमर तक पहुंचने और उनसे प्रॉडक्ट या सर्विस के बारे में उनकी प्रतिक्रिया मांगने में मदद करता है। एक आंत्रप्रेन्योर को प्रॉडक्ट डिवेलप करने, उसे निवेशकों तक पहुंचाने और बनाने के लिए टीम तैयार करनी होती है। उसमें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि अपने विजन में सबका भरोसा जगा सके। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस न हो। अति आत्मविश्वास अक्सर गलत फैसले करवा देता है। इसलिए बैलंस बनाए रखना भी जरूरी है।

क्या आप सेल्फ मोटिवेटिड हैं?

आजादी का मतलब है वह क्षमता होना कि अकेले भी काम कर सकें और सभी काम बढ़िया तरीके से पूरे करे। एक आंत्रप्रेन्योर खुद को हमेशा मोटिवेशन से भरपूर रखता है और अपने कामों पर उसका पूरा कंट्रोल रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका कोई बॉस नहीं होता जो उसे लगातार गाइड करता रहे।

काम के लिए जुनून कितना है?

इस गुण का मतलब है कि उसे ज़िंदगी के मुश्किल वक्त में हार न मानने की आदत हो और वह लगातार आगे बढ़ता रह सकता है। कोई भी कारोबार करने में कई बार नाकामी भी मिलती है। कई बार चीजें हमारे हक में नहीं रहतीं। उस वक्त आंत्रप्रेन्योर को पॉजिटिव रहना होता है। उसका मोटिवेशन खत्म नहीं होना चाहिए। जुनून का मतलब यह भी है कि मुश्किलें दूर करने के लिए अलग और नए तरीके निकालना। पहली कोशिश में नाकामी मिलने के बावजूद निराश या दुखी न होना।

सिर्फ अपने मन की करते हैं?

यह बहुत ही जरूरी है कि दूसरों के विचारों और उनकी राय के प्रति खुलापन बरता जाए। स्टार्टअप में खुला दिमाग रखना ही फायदेमंद होता है, हर कदम पर स्मार्ट होने के लिए गलतियों से सीखना भी जरूरी है। अपनी ही नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखना होता है।

आपका काम का रवैया कैसा है?

यह क्षमता भी होनी चाहिए कि किसी खास परिस्थिति में कैसे रिऐक्ट करना होता है। आंत्रप्रेन्योर का ऐटिट्यूड ही यह तय करता है कि अगर विपरीत परिस्थिति आई या जब वक्त अपने हक में न हो तो वह कैसे काम करेगा। एक आंत्रप्रेन्योर एक एम्प्लॉई की तरह काम नहीं करता। वह खुद फैसला लेता है और दूसरों को उसे मानने के लिए मोटिवेट करता है। उसका पॉजिटिव ऐटिट्यूड उसे ही नहीं, साथ काम करनेवालों को भी खुश रखता है। क्या आप जुझारू हैं।

क्या आप क्रिएटिव हैं?

सेल्फ असेसमेंट करें और खुद से कुछ सवाल पूछें कि क्या हम बिजनेस के लिए बने हैं? क्या आप ज़िंदगी के अलग-अलग हालात में कोई परेशानी आने पर कोई ऐसा हल पेश करते हैं जिसका इस्तेमाल आसपास वाले भी करते हैं। क्या कोई मुश्किल अनसुलझी समस्या को सुलझाकर आपको गर्व महसूस होता है?

क्या आप में पर्याप्त धैर्य है?

कोई बिजनेस कितने वक्त में जमेगा, यह अलग-अलग स्टार्टअप पर निर्भर करता है। क्या आपके अंदर इतना धैर्य है कि इंतजार कर सकें? हो सकता है कि ऐप की टेस्टिंग से 4-6 महीने में ही समझ आ जाए कि स्टार्टअप आगे बढ़ेगा या नहीं। अगर सही दिशा में ग्रोथ नहीं दिख रही तो हाथ खींच सकते हैं। अगर अपना कॉन्सेप्ट समझाने में ही 2 साल लग रहे हों तो आइडिया बदल सकते हैं। लेकिन आइडिया को 6 महीने में कम से कम 100 लोगों के सामने उतार सकते हैं तो जरूर करके देखना चाहिए। वैसे तो अब ऐसे टूल भी आते हैं जो फटाफट डिजिटल स्टोर बना देते हैं। खुद के ऐप की जरूरत नहीं होती। वन-क्लिप प्लैटफॉर्म भी हैं जैसे एप्दज्ब्ि आदि। वहां यह डर भी नहीं होता कि हमारी वेबसाइट को कोई कॉपी न कर ले।

क्या रिस्क उठाने को तैयार हैं?

खुद से पूछें कि क्या आप रिस्क उठा सकते हैं। आपके घर, परिवार, हेल्थ और फाइनैंस को देखते हुए आप इसके लिए तैयार हो सकेंगे।

क्या नाकामी के लिए तैयार हैं?

एक आइडिया पर लगातार काम करना पड़ सकता है। कई बार यह सफर थकाऊ होता है। कुछ लोगों का स्टार्टअप और आइडिया बदलता रहता है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। इलॉन मस्क जैसे भी उदाहरण हैं जो एक-बार अच्छी खासी कमाई गंवाने के कगार पर पहुंच गए थे। कई बार सारी प्लानिंग के बावजूद भी कारोबार घाटे में चला जाता है। क्या आप हर बुरी स्थिति को संभालने के लिए तैयार हैं।

जब जॉब छोड़कर करना हो स्टार्टअप

नौकरीपेशा से कारोबारी बनना बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए पूरी योजना बनाकर काम करें। जॉब में एक दिन में 10-12 घंटे काम करते हैं तो हाथ में सैलरी ही मिलती है। इसी बात से मोटिवेशन आता है कि अपने लिए काम किया तो ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा। अगर टीम होती है तो उसे भी मोटिवेट करते रहना होता है। अगर कोई शख्स परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहा है तो उसे सोचना पड़ता है कि नौकरी छोड़कर काम करे या नौकरी के साथ-साथ ही काम शुरू करे। अच्छा तो यही है कि नौकरी छोड़कर ही स्टार्टअप करें लेकिन एजुकेशन लोन हो, घर की किस्ते हों या परिवार को देखते हुए नौकरी के साथ ही कर सकते हैं। रिस्क कम करने के लिए जिस क्षेत्र की जानकारी है, जिसमें काम किया है उसी क्षेत्र में स्टार्टअप करें। जैसे जिरोधा के फाउंडर पहले खुद ट्रेडिंग करते थे, ब्रोकर का काम भी करते थे, फिर उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। इसलिए अगर आपने तय कर ही लिया है कि कुछ शुरू करना है लेकिन अपनी जिम्मेदारियों की वजह से नौकरी छोड़कर नहीं कर सकते तो अपने किसी साथी या को-इन्वेस्टर को तैयार करें और इस काम में कूद पड़ें। जब काम जम जाए यानी अच्छी स्थिति में पहुंच जाए तो जॉब छोड़ दें। वैसे कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि नौकरी छोड़कर ही स्टार्टअप में जाना चाहिए। नौकरी में रहते हुए सिर्फ रिसर्च का काम करें। फिर पूरे 200 फीसदी कमिटमेंट के साथ स्टार्टअप की फील्ड में आ जाएं।

लीडरशिप सबसे अहम

- **लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता**
- **12 से 16 घंटे तक लगातार काम करने की क्षमता**
- **घर परिवार की तरफ से फ्री (वहां किसी जिम्मेदारी, बीमार आदि के लिए वक्त देने की जरूरत नहीं)**
- **रोजमर्रा की ज़िंदगी में किसी समस्या का सामना होने पर उसके हल का एकदम नया आइडिया आता हो**
- **फटाफट फैसले लेने की क्षमता**
- **रिस्क लेने की क्षमता**
- **पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं**
- **कोई बड़ा कर्ज पहले से नहीं**
- **कोई बड़ा खर्च (परिवार में किसी की पढ़ाई, शादी, बीमारी आदि पर) अभी या निकट भविष्य में नहीं**
- **वह खुद स्वस्थ हो**
- **अगर टेक पर आधारित स्टार्टअप करना है तो स्किल सेट में कोडिंग जरूर आनी चाहिए। चाहे IT की डिग्री हो या नहीं**
- **मेंटली बहुत मजबूत**
- **इमोशनल होकर फैसले न लेते हों।**

पहले से क्या तैयारी करें... क्या आप फाइनैंशली तैयार हैं?

सिर्फ स्टार्टअप की लहर के झांसे में नहीं आना। हमें वही कहानियां दिखती हैं जो सफल हैं। ऐसे भी बहुत-से लोग हैं जिनका काम नहीं चला। इसलिए सबकुछ सोचकर ही आगे बढ़ें। अगर दो-तीन साल में बिजनेस नहीं चला तो घर कैसे चलेगा। बाकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करें।

-क्या आपके पास आगे के लिए परिवार के खर्चों का ध्यान रखने के लिए बैंक में लिक्विड मनी है यानी पर्याप्त पैसा है? मान लें कि आपका महीने का खर्च 50 हजार रुपये का होता है तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि 1 साल तक आप घर खर्च के लिए परेशान न हों। सबसे अच्छा तो यह है कि 36 महीने का फाइनैंस लेकर चलें।

-आपकी EMI और देनदारियां कितनी हैं? घर या कार है? उसका लोन, मेंटिनेंस और दूसरे खर्च भी होते हैं। बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्च एजुकेशन लोन है तो उसकी किस्त चुकाने का खर्च

-क्या आपके पास पूरे परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है? किसी भी तरह के मेडिकल खर्च के लिए भी तैयार रहना होगा, इमरजेंसी के लिए पूरे परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस ले लें।

-कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस कामयाब हो रहा है लेकिन आगे उसमें लगाने के लिए पैसा नहीं है तो भी बिजनेस छोड़ना पड़ सकता है। उसकी प्लानिंग भी कर लें।

- अगर घर में पत्नी या पिता की नौकरी है या वे कोई काम करते हैं जिससे फाइनैंशल मदद मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है। नहीं अपना बैकअप जरूर रखें।

-अपना काम शुरू होगा तो उसमें पैसा लगेगा ही। टीम को सैलरी भी देनी होगी। इसलिए कोई एंजेल इन्वेस्टर खोजकर उससे पैसे लेकर रख सकते हैं। सिर्फ आइडिया के बेस पर बाहर का कोई प्रफेशनल इन्वेस्टर नहीं आएगा। ऐसे में परिवार में से, कलीग, बॉस, फ्रेंड्स से 5-10 लाख रुपये जुटा लें।

जब स्टूडेंट को करना हो स्टार्टअप

पढ़ाई में आप जैसे भी हों, अगर मेहनत और स्मार्ट तरीके से काम किया तो स्टार्टअप में बढ़िया कर सकते हैं। इसके लिए जितना जल्दी शुरुआत करें, उतना अच्छा है। फिलहाल ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें लोग पढ़ाई में पीछे थे, अच्छे इंस्टिट्यूट से एमबीए भी नहीं कर पाए या कॉलेज में बहुत बढ़िया नहीं रहे लेकिन उन्होंने किसी परेशानी का हल खोजने का अपना जुनून नहीं छोड़ा। इसलिए अगर बढ़िया आइडिया दिमाग में है तो कैंपस में ही अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ स्टार्टअप की तैयारी कर सकते हैं। नौकरी में अपने को-वर्कर के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। कुछ साल पहले कॉलेज में टीम बनाकर कई स्टूडेंट्स ने जो स्टार्टअप शुरू किए थे वे आज काफी अच्छा कर रहे हैं। यह मुद्दा भी नहीं रहता कि सामनेवाला भरोसेमंद है या नहीं। अगर टेक्निकल फील्ड में हैं या कोडिंग आदि आती है तो अपना ऐप लॉन्च कर सकते हैं। वेबसाइट बना सकते हैं। कुछ हजार रुपये में यानी कुल 10 हजार रुपये से ही एक स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। हो सकता है कि वह हिट हो जाए।

सीधे स्टार्ट हो जाएं या पहले जॉब

अगर ज्यादा जानकारी और अनुभव के साथ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो जब स्टूडेंट है तभी उसी फील्ड में इंटर्नशिप करें जिसमें आपको स्टार्टअप लाना है। आजकल स्टार्टअप वाली बहुत-सी कंपनियां इंटर्नशिप ऑफर करती हैं। नौकरी इसलिए करें कि इस बात का तजुर्बा हो जाए कि आगे अपने काम को कैसे अंजाम देंगे। किस तरह कोई स्टार्टअप चलाया जा रहा है, इसे सीखने के लिए सीधे मार्केट में उतरना चाहिए। अगर किसी को कंस्यूमर इंटरनेट पर काम करना है और उसे नहीं पता कि उस फील्ड में कैसे काम होता है, कैसे समस्या हल की जाती है तो अपना स्टार्टअप कैसे चलाएंगे। जब स्टार्टअप की तैयारी करे तो नेटवर्किंग पर ध्यान देना शुरू कर दें। आगे चलकर अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। किसी छोटी कंपनी में इंटर्नशिप करेंगे तो वहां हर रोल में ज्यादा सीखने को मिलेगा। आगे चलकर नौकरी में भी उसका फायदा मिलेगा। इससे स्किल भी डिवेलप हो जाते हैं।

शादी की तरह ही है स्टार्टअप

स्टार्टअप के लिए अलग-अलग मॉडल होते हैं। यह शादी की तरह होता है। सही पार्टनर मिल जाए तो शादी की तरह स्टार्टअप भी बढ़िया चल जाता है। वहीं, सोलो और पार्टनर का जहां तक सवाल है तो यह बच्चा पालने की तरह है क्योंकि बच्चे को सिंगल पैरेंट भी पाल सकता है लेकिन कई लोगों का साथ मिलता है तो सबके अनुभव का फायदा मिल जाता है। वैसे हर बिजनेस अकेले नहीं किया जा सकता। कुछ काम पार्टनर के साथ ही बढ़िया होते हैं।

स्टार्टअप पर सरकारी पहल

साल 2017 के बाद से स्टार्टअप की परिभाषा बदली है। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके लिए अपने स्टार्टअप का startup.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर भारत

अब बजट 2023 से पहले आ रही यह मांग

नई दिल्ली । एजेंसी

वाधवानी फाउंडेशन ने कहा कि सरकार को देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर टैक्स छूट देने पर विचार करना चाहिए। अपनी बजट इच्छा सूची में वाधवानी फाउंडेशन ने यह बात कही है। वाधवानी फाउंडेशन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्टार्ट-अप का संचालन करता है। फाउंडेशन के सीओओ (भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया) संजय शाह ने कहा, चूंकि भारतीय स्टार्ट-अप तेजी से वैश्विक हो रहे हैं, इसलिए सरकार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कर छूट (Tax Exemption) पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स की संख्या को देखते हुए केवल अमेरिका और चीन भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम से आगे हैं।

भारत में हैं 400 से अधिक इनक्यूबेटर

भारत में 400 से अधिक इनक्यूबेटर हैं, जो महत्वपूर्ण संसाधन और सेवाएं प्रदान करने में सहायक रहे हैं। जैसे कि सलाहकारों और निवेशकों तक पहुंच, एक मजबूत व्यवसाय योजना बनाना, साझा प्रशासनिक सेवाएं, नेटवर्किंग और स्टार्टअप्स के लिए उत्पाद लाइनों पर विशेषज्ञ सलाह आदि। साल 2025 तक 250 यूनिकॉर्न के साथ अभी 100 से थोड़ा अधिक और 2023 तक कुल 180 अरब डॉलर की फंडिंग के साथ भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक बेहतर स्थिति में है। शाह ने कहा प्रदर्शित क्षमताओं वाले ग्रोथ-स्टेज स्टार्टअप्स को अनुसंधान और विकास, प्रोटोटाइप तथा उत्पाद परीक्षणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

तेजी से बढ़ रही यूनिकॉर्न की संख्या

स्टार्टअप इकोसिस्टम की हालिया जीवंतता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत को 100 यूनिकॉर्न प्राप्त करने में लगभग सात से 10 साल लगे। वहीं, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 100 अन्य तीन से चार वर्षों में आएंगे। शाह ने आगे कहा, 'हम अगले 100 तक पहुंचेंगे, क्योंकि अब ये टियर-2 और टियर-3 शहरों में फैल रहे हैं। हम छोटे शहरों से अधिक स्टार्टअप देखेंगे। यह पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर हैंडहोल्डिंग और राजकोषीय और नीतिगत प्रोत्साहन प्रदान करने की मांग करता है।

49 फीसदी स्टार्टअप टियर-2 और टियर-3 शहरों से

भारत के 60,000 स्टार्ट-अप में से लगभग 49 फीसदी टियर-2 और टियर-3 शहरों से हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम 2016 और 2022 के बीच तेजी से बढ़ा। लगभग 63 अरब डॉलर के निवेश के साथ 2021 भारत में निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निवेश के मामले में एक सफल वर्ष था। उपभोक्ता, वित्तीय सेवाओं, रसद, कृषि आदि की ओर प्रौद्योगिकी डोमेन से परे कई स्टार्ट-अप के साथ स्पेस अधिक से अधिक व्यापक हो गया। शाह ने कहा कि भारत अपनी महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं और 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की आकांक्षाओं का अनुसरण कर रहा है। इसके सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में उद्यमियों की बढ़ती हिस्सेदारी भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाएगी।

रूपया आठ पैसे टूटकर 82.86 प्रति डॉलर पर

मुंबई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रूपया मंगलवार को आठ पैसे की गिरावट के साथ 82.86 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ। विदेशों में डॉलर के मजबूत होने और विदेशी पूंजी की सतत निकासी के कारण रूपये में गिरावट आई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रूपया 82.69 के स्तर पर सकारात्मक रख के साथ खुला लेकिन बाद में यह 82.92 प्रति डॉलर के दिन के निचले स्तर को छू गया और कारोबार के अंत में आठ पैसे की गिरावट के साथ 82.86 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

अब आप पिएंगे रिलायंस की सॉफ्ट ड्रिंक

100 साल पुरानी कंपनी में खरीद रही हिस्सेदारी, कोक-पेप्सी को मिलेगी टक्कर

नई दिल्ली । एजेंसी

मुकेश अंबानी की अगुआई वाली रिलायंस एफएमसीजी सेक्टर में अपने पैर मजबूती से जमा रही है। कैंपा कोला के बाद अब रिलांयस ग्रुप एक और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रही है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (RCPL) सोस्यो हजूरी बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड (SHBPL) में 50 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी। यह गुजरात की कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स (CSD) और जूस बनाने वाली कंपनी है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज की एफएमसीजी शाखा है। यह देश की प्रमुख रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड (RRVL) की सब्सिडियरी है। आरआरवीएल ने मंगलवार को एक बयान में कहा की यह अधिग्रहण आरसीपीएल को अपने बेवरेजेज पोर्टफोलियो को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। बता दें कि आरसीपीएल लोटस चॉकलेट में भी नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल कर रही है।

100 साल पुरानी कंपनी है सोस्यो हजूरी

सोस्यो हजूरी बेवरेजेज (Sosyo Hajoori Beverages) 100 साल पुरानी पेय प्रोडक्ट निर्माता कंपनी है। कंपनी के मौजूदा प्रमोटर्स हजूरी परिवार के पास एसएचबीपीएल की शेष हिस्सेदारी बनी रहेगी। बयान में कहा गया, 'इस जॉइंट वेंचर के साथ रिलायंस बेवरेजेज के सेगमेंट में अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगा। यह पहले से ही जाने-माने ब्रैंड कैम्पा का अधिग्रहण कर चुका है। इसके अलावा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और उपभोक्ताओं के लिए अद्वितीय वैल्यू ऑफर डेवलप करने के फॉर्मूलेशन में सोस्यो की एक्सपर्टीज का लाभ उठाया जा सकता है।'

अब्बास अब्दुल रहीम हजूरी ने की थी स्थापना

सोस्यो हजूरी की स्थापना साल 1923 में अब्बास अब्दुलरहीम हजूरी ने की थी। यह सोस्यो ब्रैंड के तहत अपने बेवरेजेज बिजनस का संचालन करती है। यह कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूस के बिजनस में देश की प्रमुख कंपनियों में से एक है। इस कंपनी के बेवरेजेज पोर्टफोलियो में कई ब्रैंड्स हैं।

इनमें सोस्यो, कश्मीरा, लेमी, गिनलिम, रनर, ओपनर, हजूरी सोडा के साथ-साथ करीब 100 फ्लेवर शामिल हैं।

सोस्यो को मिलेंगे विकास के नए अवसर

इस इन्वेस्टमेंट पर रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा, 'ये जॉइंट वेंचर हमारी उस सोच को दिखाता है जिसके तहत हम देश के स्थापित ब्रैंड्स और स्थानीय कारोबारों को ग्रोथ के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। हम 100 साल पुरानी कंपनी सोस्यो की विरासत को अपने कंज्यूमर ब्रैंड पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमारे कंज्यूमर बेस और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत से सोस्यो को विकास के नए अवसर मिलेंगे।'

चीनी उद्योग से जुड़ी इस कंपनी के शेयर ने किया मालामाल

नई दिल्ली । एजेंसी

द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड चीनी और इससे जुड़े उत्पादों के उत्पादन के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी की इथेनॉल और औद्योगिक अल्कोहल उत्पादन में मजबूत उपस्थिति है। कंपनी की प्रोडक्ट रेंज में चीनी, सफेद क्रिस्टल चीनी, इथेनॉल, कैप्टिव पावर और गुड़ शामिल हैं। कंपनी की उत्तर प्रदेश में तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और यह भारत में चीनी क्षेत्र की एक जानी-मानी कंपनी है। गुरुवार को द्वारिकेश शुगर का शेयर 104.30 रुपए पर ट्रेड करता दिखा। इस तरह इसने पिछले दो वर्षों में 200 फीसदी रिटर्न दिया है। यह स्टॉक 30 दिसंबर, 2020 को 31.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इस तरह दो साल की होल्डिंग अवधि में इस शेयर ने शानदार रिटर्न दिया है। जबकि एसएंडपी बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स ने पिछले दो वर्षों में 55% से अधिक रिटर्न दिया है। समेकित आधार पर हालिया तिमाही परिणाम में कंपनी का शुद्ध राजस्व साल दर साल 6.79% बढ़कर 540.11 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के खर्चों में वृद्धि के कारण कंपनी का मुनाफा साल दर साल 80% घटकर 7.84 करोड़ रुपये रहा। स्टॉक इस समय 11.3x के इंडस्ट्री पीई के मुकाबले 14.2x के टीटीएम पीई पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने 24% और 21% का ROE और ROCE हासिल किया है। इसका बाजार पूंजीकरण 1962.10 करोड़ रुपये है। आज इस कंपनी का शेयर 99.40 रुपये पर खुला। बीएसई पर स्टॉक का 52-सप्ताह का उच्च और निम्न स्तर क्रमशः 148.45 रुपये और 70.90 रुपये है।

सनातन धर्म

अकेला देश जहां हिंदू कैलेंडर से चलता है कामकाज, नहीं मानते ग्रेगोरियन पद्धति

पूरी दुनिया ने वर्ष 2022 को अलविदा कहते हुए 2023 का नए साल के तौर पर स्वागत किया है. दुनिया के 200 से ज्यादा देश ग्रेगोरियन कैलेंडर ही मानते हैं. मतलब वहां सारे काम काज सरकारी तौर पर जनवरी से शुरू होकर

दिसंबर तक चलते हैं. हर प्रक्रिया में सबकुछ इसी कैलेंडर से चलता है. यहां तक की विक्रम संवत कैलेंडर की रचना करने वाला भारत भी हर कामकाज में ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही प्राथमिकता देता है लेकिन दुनिया का एक ऐसा देश भी है, जहां ग्रेगोरियन नहीं बल्कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कामकाज चलता है.

हालांकि वर्ष 1954 से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की सरकार ने हिंदू कैलेंडर यानि विक्रम संवत को ग्रेगोरियन फारमेट के साथ अपना लिया था लेकिन देश का सारा कामकाज ग्रेगोरियन कैलेंडर फारमेट से ही होता है. नेपाल ने हमेशा हिंदू कैलेंडर को ही माना है.

इसे विक्रमी कैलेंडर भी कहते हैं. ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है. इसे विक्रम संवत कैलेंडर भी कहते हैं.

करीब 57 ईसा पूर्व से ही भारतीय उपमहाद्वीप में तिथियों एवं समय का आंकलन करने के लिए विक्रम संवत, बिक्रम संवत अथवा विक्रमी कैलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है. ये यह हिन्दू कैलेंडर नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर है. वैसे भारत के कई राज्यों विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है.

नेपाल में 1901 से आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल

नेपाल में आधिकारिक तौर पर विक्रम संवत कैलेंडर का इस्तेमाल 1901 ईस्वी में शुरू किया गया.नेपाल के राणा वंश द्वारा बिक्रम संवत को आधिकारिक हिंदू कैलेंडर बनाया गया. नेपाल में नया साल बैशाख महीने (ग्रेगोरियन कैलेंडर में 13-15 अप्रैल) के पहले दिन से शुरू होता है. चैत्र महीने के आखिरी दिन के साथ समाप्त होता है. नए साल के पहले दिन नेपाल में सार्वजनिक अवकाश होता है.

ये चांद की स्थितियों के साथ सौर नक्षत्र वर्ष का भी उपयोग करता है. विक्रम संवत कैलेंडर का नाम राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया था, जहां संस्कृत शब्द 'संवत' का प्रयोग 'वर्ष' को दर्शाने के लिए किया गया है. विक्रमादित्य का जन्म 102 ईसा पूर्व और उनकी मृत्यु 15 ईस्वी को हुई थी.

57 ईसा पूर्व में भारतवर्ष के प्रतापी राजा विक्रमादित्य ने देशवासियों को शकों के अत्याचारी शासन से मुक्त किया था. उसी विजय की स्मृति में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से विक्रम संवत की भी शुरुआत हुई थी.

इसमें भी 12 महीने का एक साल और 07 दिन का हफ्ता

इस संवत् का आरम्भ गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से और उत्तरी भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है. बारह महीने का एक वर्ष और सात दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत् से ही शुरू हुआ. महीने का हिसाब सूर्य व चन्द्रमा की गति पर रखा जाता है.

ये 12 राशियां 12 सौर मास हैं. पूर्णिमा के दिन, चन्द्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी आधार पर महीनों का नामकरण हुआ है. चंद्र वर्ष, सौर वर्ष से 11 दिन 3 घटी 48 पल छोटा है, इसीलिए प्रत्येक 3 वर्ष में इसमें 1 महीना जोड़ दिया जाता है.

क्यों ये बेहतर है

विक्रम संवत में कई ऐसी बातें हैं जो इसे अंग्रेजी कैलेंडर से ज्यादा बेहतर बनाती हैं. हिन्दुओं के सभी तीज-त्यौहार, मुहूर्त, शुभ-अशुभ योग, सूर्य-चंद्र ग्रहण, हिन्दी पंचांग की गणना के आधार पर ही तय होते हैं. इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक महत्वपूर्ण काम की शुरुआत हिन्दी पंचांग से मुहूर्त देखकर ही की जाती है.

तब संवत शुरुआत के लिए विक्रमादित्य ने माफ किया पूरी प्रजा का ऋण

विक्रम संवत के जनक विक्रमादित्य राजा भर्तृहरि के छोटे भाई थे. भर्तृहरि को उनकी पत्नी ने धोखा दिया तो उन्होंने राज्य छोड़कर संन्यास ले लिया. राज्य सौंप दिया विक्रमादित्य को. ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा का पूरा ऋण माफ कर दिया था, ताकि लोगों की आर्थिक दिक्कतें खत्म हो जाएं. उस समय जो राजा अपनी प्रजा का पूरा कर्ज माफ कर देता था, उसके नाम से ही संवत प्रचलित हो जाता था. इस कारण उनके नाम से विक्रम संवत प्रचलित हो गया.

विक्रम संवत से पहले कौन सा पंचांग चलता था

करीब 5 हजार साल पहले यानी द्वापर युग से भी पहले सप्तऋषियों के नाम से संवत चला करते थे. द्वापर युग में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ. इसके बाद श्रीकृष्ण के नाम से संवत प्रचलित हुआ. द्वापर युग के बाद कलियुग शुरु हुआ था. श्रीकृष्ण संवत के करीब 3000 साल बाद विक्रम संवत की शुरुआत हुई, जो आज तक प्रचलित है.

इस साल हिंदू कैलेंडर 12 की बजाए 13 महीनों का

हिंदू कैलेंडर के मुताबिक नया साल 12 महीनों के बजाए 13 महीनों का हो सकता है. दरअसल ये अधिमास के कारण होगा. शिव का पवित्र माह सावन 30 दिन नहीं, बल्कि 59 दिनों का होगा. मतलब सावन का महीना दो माह तक रहेगा. सावन के महीने में 8 सोमवार पड़ेंगे.

नए साल में अपने घर में रखें ये 5 चीजें, कभी नहीं होगी पैसों की तंगी

धन की देवी माता लक्ष्मी की आराधना से न केवल धन बल्कि नाम और यश की भी प्राप्ति होती है. इनकी आराधना से वैवाहिक जीवन में मिठास आती है. इनकी सही विधि और नियम से आराधना की जाए तो मां धन लक्ष्मी खाली भंडार भी अन्न, धन से संपन्न कर देती हैं. कुछ शुभ चीजें भी मां लक्ष्मी को अपनी ओर सम्मोहित करती हैं. इन शुभ चीजों को अगर आप नए साल के अवसर पर अपने घर ले आएं तो ये बहुत ही शुभ फलदायी होगा. आइए आज हम आपको उन पांच चीजों के बारे में बताते हैं जिन्हें घर में रखने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है।

शंख

शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा होता है. हिन्दू पौराणिक हिन्दू मान्यता के अनुसार शंख जन्म समुद्र से माना जाता है. कहीं-कहीं पर शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं. ऐसा कहा जाता हैं कि जहां शंख होता है वहां लक्ष्मी जी अवश्य होती हैं. शुभ मंगल कार्यों के मोके पर और धार्मिक त्योहारों में इसको बजाना शुभ माना जाता है. शंख अनेकों प्रकार के होते हैं पर मुख्य रूप से बाईं ओर खुलने वाले (वामावर्ती) शंख चलन में दिखते हैं. मध्यावर्ती शंख और दक्षिणावर्ती शंख मुश्किल से उपलब्ध होते हैं और जिनका इस्तेमाल खास शुभफलदायक और लाभप्रद माना जाता है. पूजा के स्थल पर श्वेत रंग का शंख रखने और उपयोग करने से मा लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती हैं. आप भी अपने पूजाघर में शंख को जरूर स्थापित करें.

गुलाब की महक

गुलाब की खुशबू और गुलाब का फूल दोनों ही मां लक्ष्मी को अतिप्रिय हैं. रोजाना से माता लक्ष्मी को गंध या गुलाब अर्पित करने से व्यवसाय अच्छा होता है. गुलाब की पंखुड़ियों से मां लक्ष्मी का अभिषेक करने से ऋण दूर होते हैं. हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी को गुलाब की माला चढ़ाने से दरिद्रता का नाश होता है.

स्फटिक की माला

स्फटिक का संबंध शुक्र ग्रह से है और वैभव का प्रतीक है. मां लक्ष्मी के मंत्रो का जप स्फटिक की माला से ही करना चाहिए. मां लक्ष्मी को स्फटिक की माला भेंट करें. स्फटिक की माला पहनने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है.

श्री हरि विष्णु

साथ ही ऐसा भी कहा जाता हैं की मां लक्ष्मी की कृपा श्रीहरि के बिना कभी नहीं मिल सकती. घर के पूजा घर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति रखें. नियमित विधिवत इनकी आराधना करें. पूरे परिवार को धन लाभ होगा और आपसी स्नेह बना रहेगा. भगवान विष्णु की आराधना के लिए आप ग्यारस का उपवास भी रख सकते हैं.

घी का दीपक

मां महालक्ष्मी की पूजा के वक़्त घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए. यह दीपक चार मुखी हो तो बहुत ही उत्तम होता हैं. इसे श्वेत धातु या मिटटी के दीपक में जलाएं. शाम के वक़्त पूजा स्थल पर घी का दीपक प्रज्वलित करने से धन की फिज़ूल बर्बादी नहीं होती.

इस राम मंदिर के अध्यक्ष हैं हनुमान और यमराज करते हैं सुरक्षा

इंदौर का निरालाधाम सचमुच निराला है. मंदिर की दीवार से लगाकर शिखर तक और खंभों से लगाकर शीशे तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ श्री राम लिखा हुआ है यानी कण-कण में भगवान राम. इतना ही नहीं, यहां दर्शन करने के लिए भक्तों को कागज पर 108 बार श्री राम लिखना होता है उसके बाद ही दर्शन होते हैं. खास बात है कि यह नियम आम लोगों से लेकर बड़े से बड़े वीआईपी पर भी लागू है

इंदौर. सनातन धर्म को मानने वाले लोग अलग-अलग तरीकों से भक्ति करते हैं. उत्तर से दक्षिण तक कोस-कोस पर भक्ति के तरीके बदलते रहते हैं. भारतीय संस्कृति में जल, थल, पेड़, पौधों से लगाकर पशुओं को भी पूजा जाता है. 33 कोटि देवी-देवताओं को मानने वाला सनातन धर्म अपने आप में बहुत समृद्ध है. आपने कई अनोखे मंदिर देखें होंगे, लेकिन न्यूज़ 18 लोकल मध्य प्रदेश के इंदार के एक ऐसे मंदिर में प्रभु राम के दर्शन करवायेगा जो अपने आप में अनूठा है.

इंदौर का निरालाधाम सचमुच निराला है. मंदिर की दीवार से लगाकर शिखर तक और खंभों से लगाकर शीशे तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ श्री राम लिखा हुआ है

यानी कण-कण में भगवान राम. इतना ही नहीं, यहां दर्शन करने के लिए भक्तों को कागज पर 108 बार श्री राम लिखना होता है उसके बाद ही दर्शन होते हैं. खास बात है कि यह नियम आम लोगों से लेकर बड़े से बड़े वीआईपी पर भी लागू है. माना जाता है कि बिना 108 बार श्री राम लिखे यहां दर्शन पूरे नहीं होते.

इस मंदिर की खास बात यह भी है कि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हनुमान हैं, कोषाध्यक्ष कुबेर हैं. तो मंदिर परिसर की सुरक्षा का जिम्मा स्वयं यमराज उठाते हैं. सेक्रेटरी भोले शंकर को बनाया गया है. तो वहीं, लेखा-जोखा चित्रगुप्त देखते हैं. इस अनोखे मंदिर में लंकापति रावण की भी पूजा होती है. भक्तों का मानना है कि रामायण का हर पात्र पूजनीय है, इसलिए रावण को भी पूजा जाना चाहिए. मंदिर परिसर में रामायण के हर पात्र की मूर्ति बनी हुई है. इन सभी पात्रों की पूजा होती है. मंदिर में हनुमान जी की कई मूर्तियां हैं, इनमें से सबसे खास 251 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई मूर्ति है जो आकर्षण का केंद्र है. वहीं, गणेश जी की एक ऐसी प्रतिमा है जिनकी सूंड से 24 घंटे शिवलिंग पर जलाभिषेक होता है.

मंदिर के अंदर रामलीला, तो मंदिर के बाहर कृष्ण का विराट स्वरूप दर्शाया गया है. मंदिर के पुजारी प्रकाश वागलेचा बताते हैं कि निराला धाम में आने वाला भक्त कभी निराश होकर नहीं लौटता. पूरे धाम के कण-कण में श्री राम बसे हैं और यहां आने वाला व्यक्ति पूरी तरह राममय हो जाता है.

दिसंबर में सरकार को मिला 15% ज्यादा जीएसटी, जानिए कितना भरा खजाना

नई दिल्ली । एजेंसी

दिसंबर में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 15 फीसदी बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। दिसंबर लगातार 10वां महीना है जब जीएसटी राजस्व 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। इससे पहले नवंबर में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 11 फीसदी बढ़कर 1.46 लाख करोड़ रुपये था। अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी संग्रह अक्टूबर में 1.52 लाख करोड़ रुपये रहा है। दिसंबर 2022 में वस्तुओं के आयात से राजस्व आठ फीसदी अधिक था और घरेलू लेनदेन से राजस्व (सेवाओं के आयात सहित) समीक्षाधीन अवधि में 18 फीसदी बढ़ा।

1,49,507 करोड़ रहा कुल जीएसटी राजस्व

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'दिसंबर 2022 के दौरान एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,49,507 करोड़ रुपये है। इसमें सीजीएसटी 26,711 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 33,357 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 78,434 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर जमा किए गए 40,263 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 11,005 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर जमा किए गए 850 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं।'

घरेलू लेनदेन से राजस्व आया 18% अधिक

दिसंबर 2021 के दौरान प्राप्त राजस्व की तुलना में वस्तुओं के आयात से राजस्व इस बार 8% अधिक था। जबकि घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व 18% अधिक था। वित्त मंत्रालय ने आगे कहा, 'सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी में 36,669 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 31,094 करोड़ रुपये का निपटान किया है। दिसंबर 2022 में नियमित निपटान के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 63,380 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 64,451 करोड़ रुपये है।'

भारत में IPhone मैन्युफैक्चरिंग से पैदा हुई 50,000 नौकरियां

नई दिल्ली । एजेंसी

आईफोन निर्माता एपल के सप्लायर्स धीरे-धीरे चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट कर रहे हैं। इसका सीधा फायदा रोजगार के मोर्चे पर भी हो रहा है। एपल के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर्स और कंपोनेंट सप्लायर्स ने भारत में 50 हजार जॉब्स पैदा किए हैं। अगस्त 2021 में स्मार्टफोन पीएलआई स्कीम आने के बाद से ये रोजगार पैदा हुए हैं। सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। डायरेक्ट जॉब्स के अलावा एपल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम से देश में एक लाख इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होने का अनुमान है। वहीं, अब आईफोन (ग्ड्प्दहा) के बाद भारत में मैकबुक और आईपैड भी बनने की तैयारी है।

सरकार को नौकरियों के आंकड़े भेजती हैं कंपनियां

भारत में एपल के आईफोन के लिए फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं। वहीं, कंपोनेंट सप्लायर्स में सुनवोडा, एवरी, फॉक्सलिंक और सालकॉम्प शामिल हैं। पीएलआई स्कीम के तहत हर लाभार्थी को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के पास तिमाही आधार पर जॉब डाटा सबमिट करना होता है। अधिकारियों ने बताया कि पीएलआई स्कीम की लाभार्थी सेमसंग ने अपनी नोएडा यूनिट में 11,500 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है।

फॉक्सकॉन दे रही सबसे ज्यादा जॉब्स

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के जरिए एपल भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ब्लू कॉलर जॉब्स का सबसे बड़ा प्रोवाइडर बन सकता है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि एपल के तीन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा क्रिएट की गई जॉब्स में 40 फीसदी से अधिक हिस्सा फॉक्सकॉन का है। फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तमिलनाडु में है। जबकि विस्ट्रॉन की कर्नाटक में है। अधिकारियों ने बताया 'कंपोनेंट्स और मॉड्यूल प्रोवाइडर्स ने कुछ हजार डायरेक्ट जॉब्स दी हैं। इन्होंने बीते 17 महीनों से एपल आईफोन सप्लाई चेन के लिए अपनी क्षमता का विस्तार किया है।'

टाटा भी दे रहा नौकरियां

टाटा ग्रुप (Tata Group) ने भी हरसौर में 500 एकड़ में आईफोन के लिए स्मार्टफोन कंपोनेंट्स बनाने के लिए प्लांट बनाया है। यहां करीब 10,000 वर्कर्स हैं। टाटा को अगले 18 महीनों में यह संख्या 45,000 तक बढ़ाने की उम्मीद है। इसके अलावा टाटा विस्ट्रॉन ग्रुप के साथ मिलकर भारत में आईफोन बनाने को लेकर भी बात कर रहा है।

चीन पर घट रही निर्भरता

इस समय एपल के तीन सप्लायर्स भारत में घरेलू बाजार और निर्यात के लिए आईफोन 11, 12, 13 और 14 बना रहे हैं। सितंबर 2022 में एपल ने ग्लोबल लॉन्च के 10 दिन बाद ही भारत में लेटेस्ट आईफोन 14 बनाना शुरू किया था। एपल भारत में अपनी मैन्यूफैक्चरिंग कैपेसिटी बना रहा है। एपल लंबे समय में चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है।

आईफोन के बाद अब भारत में मैकबुक पर नजर

भारत में सफल आईफोन प्रोडक्शन के बाद अब यहां मैकबुक और आईपैड की मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है। सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि एपल अब भारत में मैकबुक के उत्पादन के लिए भी देख रहा है। इसके लिए आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है।

सर्वे में हुआ खुलासा

दो साल में खुद का घर खरीद लेते हैं किरायेदार!

नई दिल्ली । एजेंसी

शहरों में रोजगार के तमाम अवसर होते हैं। इसी वजह से गांव और छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों की ओर जाते हैं। शहर में आने के बाद लोग किराये पर फ्लैट या मकान लेते हैं। इसके बाद शहर में वो अपना खुद का घर खरीदने की सोचने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं शहर में बाहर से रहने आए लोगों को किरायेदार से अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीदने में कितना समय लगता है? करीब 2 से 4 वर्ष। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है। सीईपीटी विश्वविद्यालय की ओर से अहमदाबाद में किराये और स्वामित्व के पैटर्न पर किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है।

इस तरह किया गया सर्वे

फैकल्टी ऑफ प्लानिंग के परास्नातक छात्र पीजी फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा थे, जहां सिटी स्टूडियो के तहत उन्होंने अहमदाबाद में पूर्वी और पश्चिमी शहर के दोनों हिस्सों में 1 वर्ग किमी के 136 ब्लॉक में और डेटा जमा करने के लिए 4,600 घरों को कवर किया है। आंकड़ों के मुताबिक, ब्लॉकों की कुल आबादी का लगभग 19 फीसदी किरायेदारों में शामिल है, लेकिन पांच क्षेत्रों - नवा नरोदा, चांदखेड़ा, सोला, थलतेज और गोटा - में लगभग 45 फीसदी या उससे अधिक आबादी किरायेदारों से बसी है। सर्वे के मुताबिक, काम करने की दूरी 50 फीसदी जगह की पसंद के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद स्कूल/शैक्षणिक संस्थान से दूरी 20%, बुनियादी ढांचा 15%, सार्वजनिक परिवहन से दूरी 12% और सामाजिक सुविधाएं 3% शामिल हैं।

ऑफिस के पास रहना पसंद करते हैं लोग

सर्वे के मुताबिक, ज्यादातर किरायेदार ऑफिस के पास रहना पसंद करते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि जहां पर वो काम कर रहे हैं उसके करीब 5 किलोमीटर तक की दूरी पर ही रहने की जगह ढूंढें। वहीं लगभग 75 फीसदी मध्यम वर्ग के किरायेदार सार्वजनिक परिवहन की तुलना में दोपहिया वाहनों से ऑफिस जाना पसंद करते हैं। इसकी वजह है कि दोपहिया वाहनों पर उनका भरोसा और कहीं भी आसानी से आने-जाने की सुविधा। इसी के चलते ज्यादातर किरायेदार दोपहिया वाहनों पर पांच गुना तक ज्यादा खर्च करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि किरायेदारों में 79 फीसदी अपार्टमेंट में रहते हैं।

पहली बार संपत्ती खरीदने वालों में 50 फीसदी किरायेदार

GIHED-CREDAI के अध्यक्ष तेजस जोशी के मुताबिक, पहली बार संपत्ति खरीदने वालों में से लगभग 50 फीसदी किराएदार हैं जो कुछ समय से शहर में रह रहे हैं। हालांकि पिछले दो वर्षों में देखा जाए तो इसमें थोड़ी गिरावट आई है। इसकी वजह ब्याज दरों में बढ़ोतरी होना है। इसके चलते ईएमआई किराये की तुलना में थोड़ी ज्यादा हो गई है। हालांकि 30 से 50 लाख रुपये तक की किफायती संपत्ती खरीदने वालों में वो लोग आगे हैं जो किराये के घर में रहते हैं, अब वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं।

इन जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदना पसंद कर रहे लोग

रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा समय में शेला, साउथ बोपल, शिलाज, वैष्णोदेवी सर्किल और पश्चिमी तरफ जुंदाल और पूर्वी तरफ निकोल ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग प्रॉपर्टी खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक, अहमदाबाद की जीडीपी पुणे (92 बिलियन डॉलर) और हैदराबाद (75 बिलियन डॉलर) से करीब 68 बिलियन डॉलर पीछे है। इसकी मुख्य वजह युवा युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने में असमर्थता है जो आमतौर पर संपत्ति खरीद के साथ बसने की तुलना में किराये के परिसर में रहना पसंद करते हैं। मूल रूप से पाटन के रहने वाले कुशाल मोदी बताते हैं कि वह साल 2012 में एक आईटी फर्म में नौकरी करने के लिए अहमदाबाद आए थे। यहां पर पांच साल तक नौकरी करने के बाद जब उनकी कुछ सैलरी बढ़ गई तो उन्होंने सेटल होने का फैसला किया। इस दौरान उनकी शादी भी होनी थी। यह भी घर खरीदने की एक वजह थी। इसके बाद उन्होंने साल 2018 में वैष्णोदेवी सर्किल के पास एक प्रॉपर्टी खरीदी।

मॉस्को सिटी ने भारतीय दर्शकों के ध्यान में रख हॉलिडे सीजन उत्सव शुरू किया

दुनिया के सभी कोनों से मस्कोवियों और मेहमानों पंहुचे

नई दिल्ली । आईपीटी नेटवर्क

मॉस्को एक उत्साहपूर्ण और चमकदार गंतव्य में बदल गया है, जो त्योहारों के मौसम के अपने कार्यक्रम 'क्रिसमस की यात्रा' की शुरुआत का प्रतीक है। शहर जादुई उत्सव स्थानों, गतिशील स्थलों, सजावट, प्रकाश व्यवस्था, पारंपरिक शीतकालीन खेल गतिविधियों और फादर फ्रॉस्ट और स्नेगुरोचका, या स्नो मेडेन से मिलने का जश्न मनाता है। यह महोत्सव 8 जनवरी 2023 तक जारी रहेगा।

इस बड़े पैमाने पर आयोजन ने शहर को क्रिसमस और नए साल के उत्सव के साथ बदल दिया है। टिमटिमाती रोशनी सड़कों को रोशन करती है, जबकि आइस-स्केटिंग रिंक और स्लाइड हर जगह पॉप अप होते हैं। पूरे परिवार के आनंद लेने के लिए लाइव संगीत प्रदर्शन और भी बहुत कुछ हैं। सभी स्थान स्वादिष्ट भोजन से भरे पड़े हैं और छुट्टियों के उत्साह से सराबोर हैं। गतिविधियां न केवल शहर के केंद्र में बल्कि दूर के नगरों में भी होती हैं। यह आयोजन मस्कोवियों और शहर के मेहमानों - युवा और वृद्ध दोनों के बीच उस जादू और छुट्टी के उत्साह को जगाने वाले उत्सव की शुरुआत को चिह्नित करता है।

दुनिया भर से लोग हर साल मास्को के विभिन्न हिस्सों में उत्सव का माहौल बनाने वाले मेलों में भाग लेते हैं। शुरुआती सुबह अद्भुत होती है, लेकिन सबसे जादुई क्षण शाम को आते हैं जब चारों ओर हजारों रोशनी जलाई जाती है और कीनू और क्रिसमस बेकिंग की सुगंध हर जगह फैल जाती है।

वे मेहमानों के लिए इसे गर्म बनाने के लिए गर्म चाय भी डालते हैं और क्रिसमस के बाजारों में घूमने में मज़ा आता है। कोई भी गैस्ट्रोनोमिक यात्रा पर जा सकता है क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों से राष्ट्रीय व्यंजन प्रदर्शित हैं और आप उन्हें चखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा, आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए नए साल के तोहफे के रूप में हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद खरीद सकते हैं। इस बार, 32 त्योहार स्थल हैं। क्रिसमस के कार्यक्रम मास्को के सभी जिलों में होते हैं। मेहमानों के लिए 4,200 मास्टर क्लास तैयार किए गए हैं और 19 रिंक खोले गए हैं, जबकि बहुत कुछ आपके एक्सप्लोर करने के लिए इंतजार कर रहा है!

यात्रा के लिए देश के खुलने के साथ, यह छुट्टियों का मौसम अतिरिक्त-विशेष और अतिरिक्त-व्यस्त होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 के लिए अपने वैश्विक शहरों की रैंकिंग में मॉस्को को जीवन की गुणवत्ता के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर नामित किया है। इसकी सुंदरता निर्विवाद है, लेकिन, सर्दियों में, शहर और भी भयानक दिखता है और मास्को उत्सव के आनंद को साझा करने के लिए सभी को आमंत्रित करने में प्रसन्न होता है।

एयरटेल 5जी प्लस अब इंदौर में

सभी 5जी स्मार्ट फोन पर काम करेगा, तेज गति व सबसे अच्छी आवाज की गुणवत्ता सिम को बदलने की जरूरत नहीं, मौजूदा एयरटेल 4जी सिम, 5जी इनेबल्ड है। रोल आउट पूरा होने तक सभी मौजूदा प्लान 5जी पर कार्य करेंगे।

इंदौर । आईपीटी नेटवर्क

भारत की अग्रणी टेलिकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर भारती एयरटेल ('एयरटेल') ने आज इंदौर में अपनी अत्याधुनिक 5जी सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की। जैसे जैसे कंपनी अपने नेटवर्क का निर्माण और रोल आउट पूरा कर रही है, एयरटेल 5जी प्लस सेवाएं चरणबद्ध तरीके से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगी। 5जी- सक्षम डिवाइस वाले ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के तेज़ एयरटेल 5जी प्लस नेटवर्क का उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक कि रोलआउट अधिक व्यापक न हो जाए। एयरटेल की 5जी प्लस सेवाएं आज से इंदौर के विजय नगर, रसोमा चौक, बॉम्बे हॉस्पिटल स्क्वायर, रेडिसन स्क्वायर, खजराना एरिया, सदर बाजार, गीता भवन, पंचशील नगर, अभिनंदन नगर, पत्रकार कॉलोनी, यशवंत रोड, फीनिक्स सिटाडेल मॉल सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर उपलब्ध है। एयरटेल पूरे शहर में अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए तेजी से अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है।

लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए, सुजय चक्रवर्ती,सीईओ, भारती एयरटेल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने कहा,'मैं इंदौर में एयरटेल 5जी प्लस के लॉन्च की घोषणा करते हुए रोमांचित हूं। एयरटेल के ग्राहक अब मौजूदा 4जी स्पीड से 20-30 गुना अधिक तक की गति के साथ एक अल्ट्राफास्ट नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं। हम पूरे शहर में इसका विस्तार करने की प्रक्रिया में हैं जो हमारे ग्राहकों को गेमिंग, मल्टीपल चैट, इंस्टेंट फोटो अपलोड और एचडी वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी गतिविधियों के लिए सुपरफास्ट एक्सेस प्रदान करेगा।'

सम्पूर्ण एयरटेल सर्विस पोर्टफोलियो को एयरटेल 5जी प्लस का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, यह एचडी वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, मल्टीपल चैट, इंस्टेंट फोटो अपलोड और अन्य गतिविधियों के लिए अविश्वसनीय रूप से तेज़ एक्सेस सक्षम करेगा। इस लॉन्च के परिणामस्वरूप, एयरटेल 5जी प्लस भारत में मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। बीते एक वर्ष में विभिन्न प्रकार के उन बेहद असरकारक उपयोग के मामलों में एयरटेल ने 5जी की अपनी क्षमता प्रदर्शित की है, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन और बिजनेस करने के तरीके दोनों को बदल देंगे। हैदराबाद में भारत के पहले लाइव 5जी नेटवर्क, भारत के खेल को बदलने वाले ऐसे क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच का 5जी पावर्ड होलोग्राम, जो उस समय खेला गया, जब उसकी टीवी कवरेज नहीं हुई थी, भारत की पहली 5जी कनेक्टेड एम्बुलेंस का निर्माण और कारखाने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बॉश के परिसर में भारत का पहला निजी 5जी नेटवर्क स्थापित करना, हर जगह एयरटेल 5जी इनोवेशन के मामले में आगे रहा है।

जनवरी में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक

नई दिल्ली। नए साल के शुरूआत के साथ ही बैंकों की छुट्टियों की नई लिस्ट सामने आ चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (ंघ)द्वारा बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट को अगर देखें तो जनवरी 2023 में बैंक 14 दिन बंद रहेंगे। इसमें रविवार और दो शनिवार की छुट्टी भी शामिल है। ऐसे में अगर नए साल में आपको बैंक जाना है तो घर से निकलने से पहले बैंक की छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें। हालांकि ये बता दें कि ये छुट्टियां देशभर के बैंकों में एक साथ नहीं है। यानी कुछ छुट्टियां अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग होती है। राज्यों के त्योहारों और प्रमुख जयंती के मुताबिक उन राज्यों में उस दिन बैंक बंद रहते हैं। जनवरी 2023 में बैंकों की लंबी छुट्टी रहने वाली है। आरबीआई की वेबसाइट पर जारी बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा बैंक निम्नलिखिति दिन बंद रहने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि बैंकों की छुट्टियों के दौरान आप ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, एटीएम सर्विस आदि का इस्तेमाल 24 घंटे कर सकते हैं।

सोनी WF-LS900N सुविधा और प्रदर्शन के बीच सही संतुलन

इंदौर । आईपीटी नेटवर्क

सोनी WF-LS900N जापानी कंपनी का नवीनतम ट्रू वायरलेस ईयरबड है। WF-1000XM4 के साथ उद्योग में अग्रणी नॉयज कैंसिलिंग और लिंकबड्स (WF-L900) के साथ पूरी तरह से जागरूक डिजाइन लाने के बाद, Sony WF-LS900N के साथ एक मध्य मैदान खोजने की कोशिश कर रहा है। सरल शब्दों में, सोनी ने उन ईयरबड्स से सर्वश्रेष्ठ लिया और उन्हें मध्य-श्रेणी की कीमत के ऑफर में पैक करने की कोशिश की।

WF-LS900N का उद्देश्य एक वास्तविक वायरलेस ईयरबड बनना है जिसमें लिंकबड्स की तरह एक मौलिक डिज़ाइन नहीं है। दूसरे शब्दों में, इसमें सिलिकॉन टिप्स के साथ एक पारंपरिक डिजाइन और विस्तारित सुनने के लिए एक आरामदायक फिट है। यह साउंड क्वालिटी या नॉइज़ कैंसलेशन के साथ 1000XM4 के स्तर तक नहीं पहुंचता है, लेकिन एक संतुलन प्रदान करता है जिसे अधिकांश लोग पसंद करेंगे। क्या WF-LS900N के लिए सोनी का अब तक का सबसे बहुउपयोगी टीडब्लूएस ईयरबड बनने के लिए इतना काफी है? लॉन्च के समय सोनी तीन रंगों में WF-LS900 पेश करता है: मटमैला, सफ़ेद और काला। इन ईयरबड्स में एक टेक्सचर्ड फिनिश है जो हाथ में एक शानदार अनुभव प्रदान करता है, और उपभोक्ताओं की खुशी के लिए, यह उन उंगलियों के निशान को समाप्त करता है जो इन फॉर्म फैक्टर में आम हैं। सभी तीन मॉडल शानदार दिखते हैं, सफेद मॉडल साफ-सुथरा दिखता है, काला रंग मजबूत होता है, और मटमैला रंग आनन्ददायक होता है। यह Sony का अभी तक का सबसे परिशोधित डिज़ाइन है और दिखाता है कि WF-1000XM3 दिनों से सोनी की डिज़ाइन भाषा कितनी विकसित हुई है।

इस साल 90 हजार पहुंचेगी चांदी, बंपर मिलेगा रिटर्न

नई दिल्ली । एजेंसी

पिछले साल दुनिया के कई देशों में महंगाई 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। इसे कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में भारी बढ़ोतरी की। केंद्रीय बैंक अभी भी ब्याज दरों में इजाफे को लेकर अपने रुख पर बरकरार है। इससे साल 2023 में मंदी की आशंकाएं पैदा हो गई हैं। जब भी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आती है तो सोने-चांदी की कीमतें ऊपर जाने लगती हैं। यही कारण है कि इस साल एक्सपर्ट्स सोने-चांदी की कीमतों में भारी उछाल का अनुमान जता रहे हैं। सोने से ज्यादा तेजी चांदी में आने का अनुमान है। केडिया एडवाइजरी के अनुसार इस साल चांदी में 30 फीसदी का रिटर्न देखने को मिल सकता है। वहीं, सोने से 14 फीसदी रिटर्न मिलने की उम्मीद है।

चांदी से मिलेगा 30% का रिटर्न

क्या आप इस साल निवेश के हिसाब से सोना खरीदने की सोच रहे हैं? जरा रुकिए। सोने से ज्यादा रिटर्न आपको चांदी में देखने को मिलने वाला है। साल 2023 में सोने की तुलना में चांदी दोगुना मुनाफा दे सकती है। केडिया एडवाइजरी के एमडी अजय केडिया ने बताया कि इस साल चांदी में 30 फीसदी रिटर्न देखने को मिलेगा। इस तरह चांदी की कीमतें साल 2023 में 90,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है।

इन वजहों से आएगी चांदी में तेजी

1. डॉलर इंडेक्स 114 से गिरकर 104 पर आ गई है। डॉलर में आगे भी गिरावट रहने का अनुमान है। जब डॉलर गिरता है तो सोने-चांदी में तेजी आती है। डॉलर में यह गिरावट चांदी में तेजी का कारण बनेगी।

2. यूएस फेड का ब्याज दरों पर आक्रामक रुख बरकरार रहने से बांड यील्ड में गिरावट आ रही है। यह चांदी की कीमतों को सपोर्ट करेगी।

3. जब भी दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव देखने को मिलता है, सोना-चांदी सेफ हैवन एसेट बनने लगते हैं। इससे कीमतों में तेजी आती है। इस समय रूस-यूक्रेन युद्ध जस का तस बना हुआ है। इसके अलवा चीन-ताइवान में भी विवाद बढ़ता जा रहा है।

4. साल 2023 में दुनियाभर में मंदी की आशंका बढ़ रही हैं। अमेरिका में मंदी आना तय है। 2023 चीन के लिए भी काफी बुरा साबित होने वाला है। आईएमएफ का अनुमान है कि इस साल एक तिहाई दुनिया मंदी की चपेट में होगी। मंदी की स्थिति में सोना-चांदी सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत होता है और कीमतों में तेजी आती है।

5. चांदी में मजबूत ईटीएफ इन्वेस्टमेंट डिमांड देखने को मिल रही है। यह डिमांड कीमतों को सपोर्ट करेगी।

6. अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में इजाफे के आखिरी चरणों में है। ब्याज दरों में इजाफा चांदी की कीमतों को ऊपर ले जाने का काम करेगा।

7. सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण में चांदी का उपयोग होते हैं। यहां से चांदी की अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। यह कीमतों को ऊपर ले जाने का काम करेगी।

8. टेलीकॉम कंपनियां 5जी टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। 5 जी टेक्नोलॉजी में चांदी का इस्तेमाल होता है। इससे भी चांदी की डिमांड बढ़ी है।

9. चांदी की इंडस्ट्रीयल डिमांड बढ़ रही है। यह बढ़ी हुई डिमांड कीमतों को ऊपर ले जाएगी।

62,000 तक जा सकता है सोना

सोने में जब भी तेजी का साइकल आता है, तो यह 2-3 साल तक चलता है। पिछले साल सोने में तेजी देखी गई थी। यह तेजी इस साल और अगले साल भी देखी जाने की उम्मीद है। साल 2022 में सोने ने 13.79 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस साल सोना 14 फीसदी का रिटर्न दे सकता है। केडिया ने बताया कि सोने के भाव इस साल 60,000 रुपये प्रति 10 तक जा सकते हैं।

ये हैं सोने में तेजी के कारण

1. साल 2023 में दुनियाभर में मंदी की आशंका बढ़ रही हैं। अमेरिका में मंदी आना तय है। 2023 चीन के लिए भी काफी बुरा साबित होने वाला है। आईएमएफ का अनुमान है कि इस साल एक तिहाई दुनिया मंदी की चपेट में होगी। मंदी की स्थिति में सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में मजबूत होता है और कीमतों में तेजी आती है।
2. डॉलर इंडेक्स 114 से गिरकर 104 पर आ गई है। डॉलर में आगे भी गिरावट रहने का अनुमान है। जब डॉलर गिरता है तो सोने में तेजी आती है।
3. जब भी दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव देखने को मिलता है, सोना-चांदी सेफ हैवन एसेट बनने लगते हैं। इससे कीमतों में तेजी आती है। इस समय रूस-यूक्रेन युद्ध जस का तस बना हुआ है। इसके अलवा चीन ताइवान में भी विवाद बढ़ता जा रहा है।
4. चीन हर साल 1000 टन सोना आयात करता है। जीरो कोविड पॉलिसी लागू होने के दौरान चीन का सोना आयात काफी गिरा हुआ था। लेकिन अब चीन अपनी बॉर्डर्स को पूरी तरह खोल रहा है। वहां जीरो कोविड पॉलिसी वापस ले ली गई है। इससे चीन में सोने की डिमांड बढ़ेगी और यह कीमतों में तेजी लाएगा।
5. भारत, चीन सहित दुनियाभर के केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं। इससे सोने की डिमांड बनी रहेगी।
6. गिरते शेयर बाजारों के चलते निवेशक इस समय दूसरे निवेश विकल्पों की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में सोने की मजबूत इन्वेस्टमेंट डिमांड बनी हुई है।
7. अमेरिकी केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में इजाफे के आखिरी चरणों में है। ब्याज दरों में इजाफा सोने की कीमतों को ऊपर ले जाने का काम करेगा।
8. भारत में जूलरी की डिमांड में रिकवरी देखने को मिल रही है। साथ ही इंडियन गोल्ड ईटीएफ का पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है। इससे कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी।
9. बढ़ती महंगाई और घटती ग्रोथ रेट से स्टैगफ्लेशन की स्थिति बन रही है। स्टैगफ्लेशन सोने को सपोर्ट करती है।

गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध, तब भी आठ महीने में 30 फीसदी ज्यादा हुआ

नई दिल्ली। इस साल देश में गेहूं के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि इस समय आम आदमी के उपयोग का खुला आटा भी 35 रुपये किलो बिक रहा है। बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इस साल मई में ही इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब भी इस साल अप्रैल से नवंबर तक गेहूं के निर्यात में करीब 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह जानकारी केंद्र सरकार के आंकड़ों से मिली है।

डेढ़ अरब डॉलर का हो गया गेहूं निर्यात

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद गेहूं का निर्यात पिछले साल से भी ज्यादा रहा है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर के दौरान यह 29.29 फीसदी बढ़ कर 1.50 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि में 1.17 अरब डॉलर के गेहूं का निर्यात हुआ था। उल्लेखनीय है कि घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि, अनुरोध करने वाले देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं के थोड़ा-बहुत निर्यात करने की अनुमति है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।